[श्री राजनारायण]

बंगला देश है, उसको फौरन मान्यता दे और इस प्रकार दो राष्ट्र का सिद्धांत दफ़ना दिया जाये।

श्रीमन्, आपकी इजाजत से मैं कहूंगा कि हमने कई बार कहा है कि एक महासंघ बने। वह महासंघ की कल्पना आज भारत की ओर से होनी चाहिए, हमने कहा था कि पश्चिमी पाकिस्तान, बिलोचिस्तान पख्तूनिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और काश्मीर इन सबका एक महासंघ बने, एक लूस कांफेड्रेशन बने।

श्रीमन्, आज एक चीज और सिद्ध हो जाती है। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, जो उर्दू को मुसलमानों से जोड़ देती हैं। (*Interruptions*) आप देखिए कि आज पूर्वी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, स्वतंत्र बंगला देश में क्या हो रहा है। वे अपनी भाषा के लिये लड़ रहे हैं। वे बंगला भाषा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसलिए मैं भारतवासियों से कहना चाहता हूं कि वे इस सदन को इंग्लिस्तान का सदन मत बनने दें। वे यहां राष्ट्र भाषा चलायें, हिन्दी चलाये, उर्दू चलायें, तमिल चलायें, तेलगू चलायें या और कोई भी भारतीय भाषा चलायें, लेकिन अंग्रेजी न चलायें। यह इंग्लिस्तान की संसद नहीं है। यह भारत की संसद है। यहां भारत की भाषाएं चलेगी। अंग्रेजी के विरोद्ध में जब हम अपनी आवाज बुलन्द करते हैं···

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : अब आप बैठ जाइये।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ· · ·

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : आपने दरख्वास्त कर ली। अब आप उसका ज्यादा फायदा उठा रहे है।

श्री राजनारायण : मेरे खिलाफ जो निन्दा का प्रस्ताव आया है, मैं चाहता हूं कि वह आज लिया जाये। हमारे लिये राष्ट्रभाषा का प्रश्न सम्मान का प्रश्न है, निन्दा का प्रश्न नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Nothing to be recorded.

(*Shri Rajnarain sat down*)

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : श्रीमन्, मुझे केवल इस अवसर पर श्री राजनारायण जी द्वारा उठाई गई दो बातों का समर्थन करना है। एक तो यह है कि यह जो कामनवैल्थ के साथ भारत जुड़ा हुआ है, अंग्रेजों का जो रवैया इस समय बंगला देश की आजादी की लड़ाई के विरोध में है, इस संसद के द्वारा मान्यता प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में भारत सरकार को राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध विच्छेद करने का निर्णय करना चाहिये।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं समर्थन में कि आज जिस स्वतंत्रता संग्राम को पूर्व बंगला देश में अंग्रेजों, चीनियों और रूसियों के हथियारों से दबाया जा रहा है, उसके जवाब में पूर्वी बंगाल मे स्वतंत्रता के लिये लड़ने वाले लोगों को भारत के शस्त्र उनकी रक्षा के लिये जरूर उपलब्ध होने चाहियें और जितने शीघ्र से शीघ्र वे पहुंचाये जा सकें, उसमें हमें जल्दी करनी चाहिये।

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*contd.*

SHRI SRIMAN PRAFULLA GOSWAMI (Assam): Mr. Vice-Chairman, with great

pleasure and pride we welcome the Address so kindly delivered by the President. I wholeheartedly support the Motion of Thanks on the President's Address.....

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (राजस्थान) : श्रीमन्, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं, तो इस समय किसी भी वरिष्ठ मंत्री को सदन में अवश्य उपस्थित रहना चाहिए। संसदीय मामलों के राज्य मंत्री हमारे सदस्य हैं और वे उपस्थित हैं, लेकिन किसी मंत्री को यहां अवश्य होना चाहिए। इतने गंभीर मामले पर राज्य सभा की उपेक्षा हो यह ठीक नहीं है। इसलिए आप किसी मंत्री को यहां बुलावें।

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) : यह राज्य सभा का अपमान है। आप प्रेसीडेंट एड्रेस डिस्कस कर रहे हैं। किसी मंत्री को यहां होना चाहिए।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : नहीं तो फिर सदन को स्थागित कर दिया जाये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Please listen to me. I appreciate your point of view. I think when we are discussing the President's Address, in addition to our friend Shri Om Mehta some Cabinet Minister should also be present here.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : विदहोल्ड दि डिस्कशन्स जब तक मंत्री नहीं आते, तब तक कार्यवाही स्थगित कर दी जाये।

SHRI A.P. CHATTERJEE (West Bengal): Let us withhold the discussion till then. Why should not a Cabinet Minister come here?

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : आप बैठिये। Order. order.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आपकी व्यवस्था डिसआर्डर क्रिएट कर रही है और आप आर्डर-आर्डर का नाम ले रहे है। जब तक कोई वरिष्ठ मंत्री यहां न हो, जो कैबिनेट में बैठता हो, यह कार्यवाही स्थगित होनी चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Please sit down. Listen to me.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): I am taking notes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : According to the norms and rules any Minister present is enough for the purpose, but as a matter of etiquette and courtesy I think a Cabinet Minister should also be present. Yes, Mr. Goswami.

श्री राजनारायण : देखिये, संसदीय प्रथा आप हमको सिखाइये नहीं। हम नहीं बैठेंगे। आप जो कह रहे हैं, वह असंसदीय है। श्रीमन्, मैं आपकी इस व्यवस्था को संसदीय परम्पराओं का अपमान समझता हूं। कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर जब राष्ट्रपति के संबोधन पर बहस हो, उसके संशोधनों पर बहस हो तो यहां रहना चाहिए। श्री ओम् मेहता कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर नहीं हैं। कैबिनेट रैंक का कोई मिनिस्टर यहां आ सकता है। इसलिए आप ऐसी व्यवस्था दीजिए कि जिसकी मान्यता हो। आप समझते है कि जो कुछ आप कह देंगे उसको हम सुन लेंगे। मैं वह सब सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। हम देश के है, हम संसद् के है और संसद् और जनतंत्रीय प्रथाओं को चलाना चाहते हैं, जो आपकी रूलिंग से दबाया जा रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान): आप बैठ जाइये।

श्री राजनारायण : क्या बैठ जाऊ। जब स्वतंत्र बगला देश पर हम बहस कर रहे है, तो आप कहते है बैठ जाइये।

श्री महावीर त्यागी : श्री मनुभाई शाह को कैबिनेट मिनिस्टर मान कर चलो।

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): As a compromise let us be satisfied with an ex-Cabinet Minister.

SHRI A.P. CHATTERJEE: Mr. Manubhai Shah is a future Cabinet Minister.

SHRI SRIMAN PRAFULLA GOSWAMI: Mr. Vice-Chairman, we welcome the Address so kindly delivered by the President. I wholeheartedly support the Motion of Thanks on the President's Address in expressing our gratefulness to the President.... (*Interruption*) I do not want interruptions. I know my duty. Please keep quiet. Please listen to what I say.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर। मैंने आपकी इजाजत से एक बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न, राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न उठाया था और मैं चाहता हूं कि आप प्रधान मंत्री को या विदेश मंत्री को बुलावें और वे बताये कि भारत की सरकार पूर्वी पाकिस्तान, स्वतंत्र बंगला देश को हथियार देने जा रही है या नहीं, उसको मान्यता प्रदान करने जा रही है या नहीं, राष्ट्र मंडल से अपना संबंध विच्छेद करने जा रही है या नहीं और इस पर बहस हो, तब आगे कोई कार्यवाही चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : आप बैठिये।

श्री राजनारायण : नहीं बैठूगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रधान मंत्री को बुलावें। वहां हमारे भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, ये हमारा खून है, हमारा रक्त एक है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): When the resolution was taken by the House you were absent.

श्री राजनारायण : हमारा रक्त है। आपने कहा है कि हम उनको मान्यता नहीं देगे। लेकिन उनका और हमारा रक्त एक है। वे हमारे भाई हैं, हमारा कुल एक है। उनकी वहां हत्या हो और हम यहां···

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Nothing to be recorded.

(*Shri Rajnarain continued to speak*)

Order, order, Please sit down.

श्री चन्द्रशेखर (उत्तर प्रदेश) : Sir, may I make a request ? मैं राजनारायण जी के लिये हिन्दी में बोलता हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजनारायण जी ने जिन भावनाओं को यहां प्रकट किया है, उससे सारे देश के लोग और इस सदन के लोग सहमत हैं। लेकिन क्या कदम सरकार उठायेगी वह निर्णय सरकार पर रहेगा। इस प्रश्न को विवाद का प्रश्न वह न बनायें तो यह बड़ी कृपा होगी। जहां तक उनकी राय की बात है, उससे हम सहमत हैं कि इस देश को हर प्रकार की सहायता श्री मुजीबुर्रहमान की करनी चाहिये। जहां तक कामनवैल्थ का प्रश्न है आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से हम कह रहे हैं कि कामनवैल्थ का ब्रिटेन के लोग नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे है। अब भी सरकार सोचे तो अच्छा है। लेकिन मैं आपके जरिये माननीय राजनारायण जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर विवाद का दूसरा अवसर है।

श्री राजनारायण : कल तो लोक सभा खत्म हो जायेगी।

श्री चन्द्रशेखर : लोक सभा खत्म होने दीजिये, हम तो बैठेंगे। वह इस प्रश्न को

विवादास्पद न बनायें और मैं समझता हूं कि राजनारायण जी हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे ।

श्री राजनारायण : मैं भाई चन्द्रशेखर जी की बात को मानने जा रहा हूं । केवल एक बात कह रहा हूं कि भाई चन्द्रशेखर जी आप देख रहे हैं कि एक तरफ सैन्य शक्ति है, एक तरफ लंका, बर्मा और चीन से सेना आ रही है और दूसरी तरफ हमारे आजादी के सैनिकों के पास हथियारों की कमी पड़ रही है । एक-एक पल की देर स्वतंत्र बंगला देश के अस्तित्व में खतरा पैदा करेगा, इसलिये उस मामले को मद्देनजर रखते हुये इसमें अरजेंसी को समझ कर, इसके लोक महत्व को समझ कर, जल्दी करिये । ठीक है ।

SHRI A.P. CHATTERJEE: Mr. Vice-Chairman Sir, one minute only; only one point. In spite of the Resolution that has been passed by this House and the other House, we have today read in the papers that the Indian Government has sealed the border between East Bengal and India. The news is this that the Indian Government has asked the police force to see that no Indian citizen must cross the border into East Pakistan and I think the order is also to this effect to see that none from that side also comes into West Bengal. I think that is merely an order for sealing the border. Will the Government of India explain that position as to why actually the border has been sealed ?

श्री राजनारायण : श्रीमन्, क्या पोजीशन है यह मैं जानना चाहूंगा ।

SHRI OM MEHTA : How is it that you are speeking again and again?

श्री राजनारायण : देखिये हल्ला मत करिये । तुम बौद्धिक परतंत्रता की बेड़ी में जकड़े हुए हो । हमने इस आजादी के लिये कुछ कुर्बानी की है । इसलिये आप इस तरह से हल्ला मत मचाओ । केवल चार पैसा इधर-उधर से जमा करके जोत कर के चले आये तो इस तरह की बातें करते हो । ठीक से बात करो ।

श्री शीलभद्र याजी : आप ठीक से बात करें ।

श्री राजनारायण : मैं यह कहना चाहता हूं···

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : आप बैठ जाइये ।

श्री राजनारायण : मैं आपके कहने से नहीं बैठूंगा । इस तरह से देश का सवाल हो और लीगल नाइसिटीज और पार्लियामेंटरी प्रोसीजर पर चलें । यह चाहेंगे कि हल्ला मचा कर हमको दबा देंगे । लाखों में वहां की जनता कत्ल हो रही है, हमको भी कत्ल कर दो तुम । क्या कर सकते हो इससे ज्यादा ?

श्री चन्द्रशेखर : माननीय वाइस चेयरमैन, राजनारायण जी से मैं कहना चाहता हूं : देश प्रेम का उन्होंने कोई ठेका नहीं लिया है । हम तो उनसे निवेदन करना चाहते हैं । हमारे निवेदन को वह स्वीकार करें ।

श्री राजनारायण : भाई चन्द्रशेखर के निवेदन को नहीं उनके हुक्म को मैं मान रहा हूं । देश प्रेम का ठेका न मैंने लिया है, न चन्द्रशेखर ने लिया है । आज इतिहास साक्षी है कि 15 अगस्त, 1947 को हमने बटवारे का विरोध किया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की पद-लिप्सा और जिन्ना की हठवादिता ने मुल्क का बटवारा कराया—दो राष्ट्रों का सिद्धांत माना, कम्युनिस्टी चाल भूपेश गुप्त की पार्टी की चली और आज इतिहास साक्षी है कि हमारी बात सही निकली ।

SHRI SRIMAN PRAFULLA GOSWAMI : We have greatest admiration for her that has demonstrated indominatable courage, conviction and determination.... *(Interruptions)*

श्री राजनारायण : सब बोलें तो बोलें लेकिन छलनी क्या बोले, जिसमें सौ-सौ छेद हैं । चाहे ओम् मेहता चिल्लाएं चाहें या भूपेश गुप्त चिल्लाएं, हम उनसे कहना चाहता है, देखिए, हम किसी के बनाए नहीं बने हैं, हम इसी भारत की धरती से बने हुए हैं ।

SHRI SRIMAN PRAFULLA GOSWAMI: First of all, Sir, I offer my heartiest congratulation to our dear leader, Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi for the greatest victory all over the country in this mid-term election decided by her. This decision for such a mid-term election was not only unusual but most daring.

Prime Minister Shrimati Indira Gandhi took such an unusual step—to quote her own words—

> "To cut through difficulties in order to solve the pressing problems with which the country is beset."

(Interruption by Shri Rajnarain)

There has been so much disturbance. The only thing is you will have to give me more time. I begin from the third paragraph,

We have greatest admiration for her that she has demonstrated indominatable courage, conviction and determination. Today we are inspired to have such a leader. We also express our deep appreciation and gratitude to the people for their wisdom and support to our leader and party expressed through the ballot boxes in this mid-term election.

What has been demonstrated in this mid-term election? Our Prime Minister wanted a mandate from the people. In her broadcast talk to the nation on December 27, she very clearly and emotionally explained the necessity of such a mid-term election. I cannot but quote some extracts from her speech. She said —

> "It is because we are not merely with remaining in power but with using that power to ensure a better life to the vast majority of our people and to satisfy their aspirations for a just social order. In the present situaion, we feel we cannot go ahead with our proclaimed pledges to our people."

While she mentioned about nation's many achievements, she has given emphasis on the goal to be achieved. She said:—

> "But despite this progress, many problems still await solution. Millions live in backwardness and poverty in towns and countryside. Justice—social economic and political—which is the basis of our Constitution, is yet a goal to be fought for and attained. Our people are 'rightly impatient' in their ardent desire for a speedier and more resolute advance towards this goal.. Time will not wait for us. The millions who demand food, shelter and jobs are pressing for action."

The people have responded to the call and reposed immense confidence in her and our party, Congress, and in our pledge. People have rejected the right reactionary, conservative forces along with left adventurists and approved of the middle path of democratic socialism chosen by our party and Prime Minister. I fully agree when my esteemed friend, Dr. Z. Ahmed, said that a national upsurge has taken place in our country. I can compare this mid-term election only with the 1946 general election on the issue of "Quit India" when people supported the Congress. But there is a a difference. Now, after independence. Indian capitalists grown to monopolists, feudal reminicent of British imperialism, have consolidated their position and have given and organised resistance to all our efforts towards progressive efforts towards building a democratic socialist state.

This is bloodless revolution through the ballot boxes. While many of our neighbouring countries have fallen under military dictatorships, our country has been able to keep up the tradition of democracy, secularism and non-alignment. For that we must congratulate the great people of our great nation. It is the people who will strengthen us and lead us on the path of peace and progress. The vested interests and the right reactionaries who want to exploit our people will be wiped out very soon. The people have become conscious and they are going to assert their rights, their legitimate rights. The Prime Minister has rightly said in our party the other day that we will have to fight a hard struggle and that this is only the beginning of our struggle against the reactionary forces who want to perpetuate our poverty and to maintain the *status quo* at all costs So, with all the emphasis at my command, I earnestly request our Prime Minister to hasten the process of socialism. She has rightly understood that the people are pressing for action. What we now want is action, action and nothing but action. We will have to fulfil our pledges. Otherwise the people will not tolerate us. We are now under a political and moral obligation to the people to establish a just social order. All the impediments, whether in the administrative machinery or in the Constitution by way of ambiguities, which stand in the way of speedy implementation of our pledges and programmes, will have to be rectified or removed ruthlessly. The interpretation of the Acts passed by the Parliament should not be with the prejudices of the judiciary but should be in conformity with the intention of the parliament. So some provisions of the Constitution must be amended, when necessary, to give clear meaning and purpose. Constitutional amendments must be brought in conformity with our declared policy of Democratic Socialism. But I must say that the amendment of the Constitution is not an end in itself; it is only a means to the end. The people are now anxiously waiting to see what action we will take to remove the poverty, disparities and the injustice that exist in our country. today. Even the mere action or step will not satisfy our rightly impatient people"; they must see the results of such action or step. I am very happy that the Prime Minister is aware of this and she has said in her call for mid-term election. We pledge our full support to carryout the struggle relentlessly until we achieve our goal. Let our leader Shrimati Gandhi speed up the process of Democratic Socialism.

I must say that since our party's acceptance of Democratic Socialism in 1964 in Bhubaneshwar, nothing tangible was done to implement the resolution till the split in the Congress. After some years again we accepted the 10-point programme in 1967 in New Delhi in the A.I.C.C. These resolutions and programmes must be implemented first to inspire the people.

The President's Address has indicated some of the immediate programmes of the Government. I entirely agree with these programmes which are of immediate importance and imperative for our country. I would like to mention some of them, on which attentions are immediately needed, like land reform, administrative machinery, rise in prices, intolerable living conditions in slum areas, improvement of housing condition in rural areas, extension of credit facilities, reorientation of the judicial system and decentralisation of power to the people instead of bureaucratisation of power.

The President has rightly referred to the administrative machinery. He has said that the Government proposes to "accelerate changes in the structure and functioning of administrative apparatus, expedite decision making, ensure effective delegation of powers and responsibilities and streamline financial procedures." This is very important. Our administrative machinery with its present pattern is an inheritance from British imperialism; I have mentioned it on earlier occasions also, and I repeat it now. I would urge the Government that first of all, the administrative machinery must be reoriented or revolutionised.

[Shri Sriman Prafulla Goswami.]

We must man the Secretariat and the Departments by people who are committed to democratic socialism; otherwise, our programmes cannot be implemented. The pattern, the system, of our administrative machinery must undergo a radical change so that it fits in with the new type of democratic socialism. In the Ministries also there should be committed persons who have proved by their past and present actions that they are genuine socialists and are prepared to execute the Government's socialist policies, without vacillation and hesitation. Socialism must be demonstrated in his profession as well as in practice.

The Government employees must undergo training about our policy and programme based on democratic Socialism.

Then, the rise in prices has been taken note of in the President's Address. I only appeal to the Government to see that the rise in the prices of foodstuffs and essential consumer goods is checked. I want to point out that food adulteration in this country has grown to such an extent that such a situation does not exist anywhere in the world. This food adulteration should be severely dealt with. The present legislation is not enough to control this food adulteration. Necessary legislation should be brought forward to impose severe punishments for food adulteration. There should also be some subsidy of food-stuffs, of essential foodstuffs, to the low-paid employees and the lower-middle classes because it is they who are hard hit by the rise in food prices. But the real producers of agricultural goods must not suffer and they must get their due price.

The President has rightly touched the problem of lawlessness. In our society today we find lawlessness and political murders. The President has rightly mentioned about the murder of Hemanta Kumar Basu, great patriot and leader of West Bengal. If we want to progress, first law and order should be established in this country so that there cannot be any scope for murder of innocent citizen, or lawlessness for creating chaos and disorder. (*Time-bell rings*) Sir, I need five minutes more because I was disturbed during my speech...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): There are many speakers. I give you three minutes more.

SHRI SRIMAN PRAFULLA GOSWAMI Then the President has mentioned about the abolition of Privy Purses of ex-rulers. Though we passed an Ordinance we could not succeed because of the Supreme Court's verdict. On the previous occasion when the Constitution Amendment Bill for the abolition of Privy Purses was discussed here I said that the ex-rulers were not entitled to get any compensation because they did not agree to the negotiations made by our leaders, particularly the Prime Minister. After the Ordinance was issued they went to the Supreme Court. In the mid-term elections also we have seen how they organised themselves to defeat our purpose and our Government. So I plead with the Government that they should not give any compensation or interim relief to the Princes. Very soon these Privy Purses and privileges should be abolished because this is a part of our mandate and such privileges were only in Feudal age; these are incompatible with modern times.

A Constitution amendment must be brought to fit the new democratic socialsim adrastic change in the role of our judicial system is also needed because our present judiciary does not conform to the declared goals of our socialism. This system of judiciary was also inherited by us from the British imperialism. I have great respect for judiciary. But the judiciary must also know the intentions of Parliament and social justice that is needed to our social order. Parliament is the supreme body which can give expression to the aspirations of the people. When Parliament passes a Bill, the judiciary should go with the intentions of Parliament. They should not twist Parliament's language and try to frustrate the Government's social objectives. Further, I want to say that justice delayed is justice denied. Thousands of cases are pending for years together in the

courts. It is only rich men who get advantage in such delay and not the poor men.

Lastly, the President's Address has mentioned about Pakistan; but when this Address was delivered, these new changes that we see today did not take place. Yesterday we passed a resolution unanimously expressing our solidarity and support to the people of East Bengal.

AN HON. MEMBER: What does that mean ?

SHRI SRIMAN PRAFULLA GOSWAMI: That means that government will follow it.

We are vitally interested in East Bengal because years ago it was part and parcel of undivided India. There was partition of our country in 1947. But the people there are blood of our blood and flesh of our flesh. We have our kith and kin there and they have their kith and kin here. There is a common bond of history, race, language, culture and traditions with East Bengal and India. Now the people there are being butchered by the military dictatorship. We were taught to fight against fascism and remove it from our political life since 1938. I do not recognise the military dictatorship as a government. Military dictator was imposed upon the people in East Bengal against the will of the people there. After the election, the people elected their representatives and they wanted to frame a new Constitution. But this is not being allowed by the military dictatorship. It is worse than Hitler's regime. Hitler had atleast some Constitutional supremacy. But this military dictator has no Constitutional supremacy over the country. He seized power by a military coup and today he is suppressing and murdering the unarmed people. It is indeed shocking how in this modern civilisation such genocide can take place anywhere in the world. Human civilisation is today in danger. From that point of view, my earnest appeal to the government is that we should mobilise world opinion against this fascist military dictatorship. We have to give these oppressed people wider help and cooperation. The whole world has to rise against the military dictatorship there. When Hitler was there with his Fascism the whole world opinion was roused against him. Today the situation is more dangerous for the human civilisation.

I hope that the government will speed up the process of socialism. Unless the process of socialism is speeded up, I am afraid people will not tolerate us. We have only five years within which we have to demonstrate our integrity and conviction. We will have to lay the foundation of democratic socialism. In this election we won because of our ideology and the Prime Minister has received the mandate from the people. The people have responded well to her call. We must therefore, go ahead with democratic socialism with speed. That is what the people expect and that why they have reposed their confidence in her. In five years we have to show to them what we are capable of doing for them. In the past long 24 years nothing much was done in this direction, though I belong to the ruling party. For the last 24 years or so we could not make revolutionary changes. Now national upsurge has taken place in our country, under the leadership of our Prime Minister Shrimati Indira Gandhi. People will support and extend their cooperation to her so that she is in a position to implement socialistic measures speedly. With these words, I support the motion of thanks.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, हमने आपको एक स्लिप भेजी थी और उसमें यह निवेदन किया था कि आप प्रधान मंत्री या सुरक्षा मंत्री को बुला लें । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कामनवैल्थ से सम्बन्ध विच्छेद नहीं किया और स्वतंत्र बंगला देश को मान्यता प्रदान नहीं की . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Your are repeating the same thing every time.

श्री राजनारायण . . . और न उसको नैतिक, भौतिक और सामरिक समर्थन प्रदान किया, इसलिए भारत सरकार की इस अकर्मण्यता और नालायकी के विरोध में मैं आज अपनी आवाज बुलन्द करने के लिये इस सदन का त्याग करता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Please sit down.

श्री राजनारायण : प्रधान मंत्री और सुरक्षा मंत्री में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे कामनवैल्थ से सम्बन्ध विच्छेद करें और स्वतंत्र बंगला देश को नैतिक, भौतिक और सामरिक समर्थन दे सकें । इसलिये इस सरकार की नालायकी और तूफान बदतमीजी के विरोध में मैं सदन का त्याग कर रहा हूं ।

(Interruptions)

(At this stage Shri Rajnarain left the Chamber)

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, this House and the other Houses in a Resolution expressed their sympathy and solidarity with our neighbours in Bengal. But I do not know whether it is just a solidarity by resolution. What are we doing ? Are we doing anything to exert our influence with some of our friendly countries ?

Sir, perhaps you are aware that recently the Soviet Union is stated to have passed on Illyushin 62 planes to Pakistan. Now, these planes are capable of a very long range—27,000 miles. These are the planes that are used for their normal service to Havana. It means that they can go round the coast of India if we do not allow them they can go round the coast of our country. Are these planes being used for this purpose? Have we lodged our protest with what is called a friendly country, with a country which is supposed to stand for peace? What are they doing ? They are trying to suppress democracy. A duly elected Government is being prevented from functioning by the military clique. And who will supply them the wherewithal to do that ? A country that we call friendly! I would like to know whether the Government has done anything. Have the Government lodged a protest, and what is the result?

Sir, this country has had an election. I do not know whether we can call it a fair election. It was an attempt to take the Opposition Parties by surprise. A statement was made in this House that Government had no intention of calling for a General Election. The Parliament was adjourned. In about a week's time, General Elections were called. I do not think this is very fair to the country. A fair way would be to give due notice and call for a General Eelection. Then, if this is to be called fair and the action of the Government is supposed to be fair, then all the actions that Government has taken after that should appear to be fair. Czar's wife should be above suspicion. Not only should the Government act fairly but its should also appear to act fairly.

Sir, the Government appointed Mr. Sen Varma as the Election Commissioner in charge of everything about the elections. Question have been asked in the other House about him. I need not repeat all that. He was subjected to a CBI inquiry : That was the answer given to a Member of Parliament in the other House. What happened to it ? But this gentleman was put in charge of the General Election. And what did he do ? He made new rules without the approval of Parliament, without the approval of even Party Leaders about how votes are to be counted and how ballot boxes should be moved. This has been considered unfair and has been protested against by several people, including myself. Sir, I have seen the President during the course of the Elections and protested against this change of rules. Also, I have seen the President

myself and drew his attention to what was being done in the course of elections.

In the neighbouring State of Rajasthan, one of the big-ups in the Congress at a meeting of the Congress workers openly said:

"मारो, काटो, जलाओ कुछ भी करो,
इन सालों को हरा दो।"

We saw the result. Within a week of that, the Maharaja of Kishangarh was murdered. Why? Because he was a Swatantra MLA and he was helping a Depressed Class member who was contesting from his constituency. Is this the way of free General Election? I drew the attention of the President to this, not only by a letter, but by personally meeting him, and all the answer that I got from him was, "If this is so, this is bad". And things went from bad to worse after that. I was present when in the Nagore constituency from which Mr. Somani, who was a member of the other House, his cars were broken up. People came with "lathies" and broke open cars. Stones were thrown on his procession. Is this the way of conducting free and fair elections

About this also I drew the attention of the President. Nothing was done. Later on some sort of protection was given to some Members. but this is not the way in which free and fair elections were conducted. On the other hand, in the neighbouring State of Bengal, we heard everyday of murders. It came nearly to one candidate being murdered everyday during the election days. Is that the free and fair election? I want to know are how people going to vote. Is the Government not aware that in certain localities, people were not allowed to go out? In certain localities, people were being evacuated because of the atrocities of the Naxalites. People were asked to pay money before they left. I drew the attention of the President and the Election Commission to this and said, what is going to happen about their votes? Is somebody going to impersonate and cast the vote on their behalf? Has any account been kept of this? Has any attempt been made to ascertain how many people left Calcutta and and nearby areas because of this terrorism and this reign of terror? No answer was received. Is this the way to conduct free and fair elections and is this the way to get a mandate?

Sir, what has happened in a place like Choti Khatu? This has been mentioned in the other House and in this House. So it. indicates how fair it was. How fair the whole compaign before and after the election was, and this is the compaign conducted to eradicate poverty. Is poverty going to be eradicated by violence? Is this the way in which the democracy is going to survive in this country?

Then, on the question of votes, what is the percentage of votes that the Congress Party has secured this time. Have they been able to secure more than what they got last time? No. They have secured less. What is the use of calling it..(*Interruptions*)

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh): How do you say that?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: The figures will be published very soon and you can see the same.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): You can go on. He will make interruptions but does not like to be interrupted.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Anyway, Sir, the fact is that less people came out to vote and this is being considered as a massive mandate. Why less people came forward to vote? It was due to terrorism. Why less people came out to vote? Then I was surprised to hear about the fairness of elections from a Member who has been sitting on the Opposite Bench, two days back. But it was pointed out to him about the ballot papers, how a large number of ballot papers unstamped, unsigned, with no mark and well numbered came out in Chandigarh. How did they

[Shri Dahyabhai V. Patel]

come? Where is the guarantee that this did not happen else where? I am referring to the State of Rajasthan. Only in the previous election, there is a judgement of the Rajasthan High Court that in the ballot box of a gentleman, Mr. Mirdha, more number of votes were found than the total number of votes on register in the constituency. This is the judgement of the Rajasthan High Court. You can find out yourself.

This same gentleman said this. I do not know whether it is justified to call him a gentleman who said:

"मारो, काटो, जलाओ, कुछ भी करो, इन सालो को हरा दो।"

Is this how free and fair elections have been conducted and is this the massive victory of the Congress and for what purpose? It is a massive victory to eradicate poverty. Is this how poverty is going to be eradicated? A normal election of the Lok Sabha and the Assemblies would have taken place next year. Under the Constitution every 5 years we have an election. This attemp to delink the to or having an early election for the Parliament has caused the exchequer quite an amount of money. What is the cost of this election? Was it necessary at all? Is this how prices are going to be brought down? You have an unnecessary election which costs crores of rupees and the candidates, of course, must have spent a lot of money, in some cases linking with the assembly elections, in some cases delinking it. The idea was perhaps to cause the maximum inconvenience to the Opposition parties. When elections are delinked, the Parliamentary candidate does not have the advantage of having the assembly candidates to cooperate with him. These are open facts. Was it the idea to seize this opportunity to deprive the Opposition Members of this? Then you will have the elections in those places where the assembly elections have not taken place very soon. By the end of the year or early next year an election will be necessary. Will that not cost money? It has caused more money to have two elections. If they are conducted together, as it has always been the case normally the elections would naturally cost less. Now these election officers, polling booths, etc. will have cost the exchequer more. Was it necessary and is this how the prices are going to come down ? When we incur unnecessary expenditure, do prices go up or come downd By simply talking of socialism and eradication of poverty, prices do not go down. Prices go down only when your production goes up . What are we doing to produce? Look at the sorry state of our public sector industries. Just before the Parliament was dissolved as a Member of the PUC I had to go to the some of the public undertakings and we saw in what sorry state they were and why. Of course in Bengal it has a special feature of labour trouble. We have built three steel plants at huge cost. One of them we have practically to write off because of constant failure of the labour. It is a very good plant. It could produce very well but we will have to write it off because the steel plant cannot remain idle for long. The furnace, if not used continuously, will get destroyed and you will have to build a new furnace. This is what has resulted. Is this going to bring down the prices? Some say that the public sector projects need not make profits. If you do not make profits, you make losses and to make the losses good, you tax the people. Is that how you bring down the prices? You cannot bring the prices down unless you produce more, you cannot bring prosperity unless you encourage thrift and you cannot encourage thrift unless you encourage people to do it. People are encouraged to save when they get returns. If they do not get returns, why should they save if they can get doles without working, why should they work at all ?

Have we enough courage to do something like that? For a long time, even the most progressive countries of the world are worried about this feature of giving doles to people who are unemployed and causing this reaction of not wanting to work. Fortunately for the countries that have advanced, they are prosperous. They can afford it.

Perhaps England can afford to give unemployment doles because they have built themselves up. They had a world of their own and empire of their own and they have a lot of saving, but what is our condition? We have no such saving. We are a poor lot. The country's production is less and the production of foodgrains is less. Fortunately it is improving now. If perhaps they had listened to me when I first talked about this ten years ago, things would have been better. When I mentioned what Taiwan had done, people said that it is a small country. When I talked of Israel, the same thing they said that it is a small country. Ultimately we have to admit that it is only because of their high production of foodgrains that they have been able to build up their prosperity. Why do we not do it? What we have done is rather low and, therefore, we are in this difficulty. Similarly, we have built up a lot of industries, but are we producing enough? Then, what has happened to our export trade? What are our exports? Are we not exporting some of the items that we need ourselves? I would like the Government to apply its mind to this fact. Why is it that most of the progressive countries of the world look to India? It is because it offers them a good market. Why do we not have that market for ourselves, instead of trying to sell more goods outside? Why do we not develop this country, put more money into the hands of the people, make the people work more and earn more produce more and spend more on their purchases? This will be a self-generating economy which can be easily achieved if we apply our mind to it. We should not hamstring the industries by all sorts of controls—sometimes necessary and sometimes unnecessary. This country is short of all kinds of metals, including brass. What an amount of brass is being exported from this country in the name of antics and earning foreign exchange? Is it necessary? Does it really build up any industry? Instead of that we should utilise it to help our industry which is suffering for want of this metal. I am just giving you a very small example. The amount of brassware that is exported from this country in the name of antics is so much and we are short of brass. Why do we all this sort of thing? This is a lopsided economy and it needs to be corrected. Has any attention been paid to it? We have diverted our attention from the main things to propaganda. Because the Swatantra Party has said this, do not do it. Well you may carry a sweeping victory, but the truth will remain. Two and two will always make four. It will not be five. If you make a promise to the people that you are going to make two and two five, you will never be able to fulfil your promise and that is what I see in this hope that is being held out to the people. This hope of removing poverty by legislation does not work and will not work. This country will have to realise it through a painful process, if we do not realise it in the normal process. Unfortunately, we have got a large illiterate population in this country and they will take a long time to become literate, but they will start feeling when the pinch comes and the pinch is bound to come very soon. You cannot postpone it till the doomsday. The pinch is bound to come. You will see the reaction of the people who were promised eradication of poverty. They were promised that you would do away with poverty and the millenium would be there. You have used the slogan "Gharibi Hatao" I would like to understand how you are going to do it, how you are going to 'Hatao Gharibi'. I do not see anything in the President's Address on these lines. On the contrary, I feell disappointed when the President had not taken any steps to ensure a free and fair election, as it should be. I have made my comments on this. I feel dissatisfied at the trend of events that are taking place elsewhere.

3 P.M.

Even if our party has not succeeded, the truth will succeed and ultimately you people will have to come round and the whole country will have to realise what is the truth.

SHRI BANKA BEHARY DAS (Orissa): Mr. Vice-Chairman, I am really grateful to you for giving me this opportunity—this

[Shri Banka Behari Das]

might be the last opportunity for me during my stay here as a Member of the Rajya Sabha.

SOME HON. MEMBERS: You will come back here again.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): I can assure you we will miss you.

SHRI BANKA BEHARI DAS: Thank you for this sentiment. Really I was not very happy to hear the President delivering his Address in a joint session of Parliament. After the massive victory of the Congress Party—it is not of the Congress Party but of Mrs. Gandhi personally—I thought the President's speech would tread some new ground because a serious challenge has been thrown and Mrs. Gandhi should have accepted that serious challenge. But I am very sorry to say that the President's speech did not give any impression to us that any new ground is going to be trodden in the coming year. Rather I was thinking, may God help democratic socialism because now ere in the President's speech, though our friends talk so much of democratic socialism, is there any mention of the word 'socialism'. That is why I am going to say that it has absolutely disillusioned me in spite of the fact that a serious challenge the Congress Party is facing. I do not know whether they are realising the great responsibility that has been thrown on them not because of their majority but because of their two-thirds majority. Now they can never find any scapegoat for their failures. They can never blame Mr. Morarji Desai that because of him the path of socialism could not be opened up before the country. No more they can say that the communal bogey that was being raised in this country is responsible for the backwardness of this country or for the the other problems confronting us from day to day.

I was much more astonshied when I heard and found some of the speeches which wanted to support the President's speech smack of arrogance. At that time I was reminded of a great statesman with whom we may not agree; he might be a symbol of imperialism but that great statesman, Wiston Churchill, just after victory in the Second World War, when he wrote his memoirs before the preface he wrote; In war, resolution, in defeat, defiance; in victory, magnanimity; in peace, good will. I would have been very happy if the President could have thought . . .

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): I do not think it is being followed here, Mr. Rajnarain showing any magnanimity.

SOME HON. MEMBERS: Victors are there.

SHRI BANKA BEHARY DAS: My friend should not forget that it is not Mr. Rajnarain who has got a thumping majority here. It is Mrs. Gandhi who has got a thumping majority. If it is a victory for them, there must be some sentiment of magnanimity. If it is a war for them, I would like that the Congress Party should take it up as a war against various problems. Then they should have shown that amount of resolution to 'hatao garibi'.

SHRI BHUPESH GUPTA: Why are you leaving us ?

SHRI BANKA BEHARY DAS: You are there to carry on the struggle if you like. Mr. Vice-Chairman, I want to say that after its victory, the war has started, and war should have shown that amount of resolution to 'hatao garibi' in this country. But I am very sorry to say that after this great victory, the President's Address has not mentioned any where the word "Socialism", nor has defined the policies which the Government can take up in the coming year. If "Garibi Hatao" was the major issue on which they fought the election, the President's Address must have shown that there is a resolution to carry it out. That is why I started by saying that it has disappointed us, it has disillusioned us.

The speech was a conventional speech. Can any of our friends here on this side

or that side tell us that the President's Address does not contain the same phraseology which has been repeated every year ? We see that his Address contains the same thing. Is there anything novel in the speech. Was not the problem of the privy purses mentioned in the last Presidential Address? Was it a new thing? Was not the question of unemployment mentioned in his last speech ? What is the novel idea that the Presidential Address contains? Has he mentioned about 'Garibi hatao' so that the Government may follow it? That is why I was rather amazed, to see that the Presidential Address gives much more importance to various other aspects, particularly to 'politics of manoeuvre'. I think think the politics of manoeuvre has started and not ended, as the President has said. When the President's Address was being drafted or when the Cabinet was going to approve of it, the politics of manoeuvre had just started. I would have been very happy if, with this assured majority of two-thirds, the politics of manoeuvre would have ended. The President had not the courage to say even about the defection that is taking place in this country. Is it not a fact that just a few days before Parliament was dissolved, the Prime Minister of India called a meeting of the Opposition leaders and gave an indication about checking defections, for a constitutional amendment? Where has that constitutional amendment gone ? The President even in his Address did not say that in the coming year—in spite of the fact that they have got a two-thirds majority—they are going to have a constitutional amendment to check defections. I would have been very happy if that were so. Mr. Mohan Kumaramangalam is here. He was on the Committee on Defections also. He also gave certain recommendations at that time. After he became a Cabinet Minister he must have at least approved the draft of the Address of the President. But I do not know whether he raised his voice at the Cabinet meeting about this assurance that has been given to the Indian nation. That point should have been mentioned in the President's Address.

SHRI BHUPESH GUPTA: you were at that meeting. You will remember that at that meeting it was suggested that a law be immediately passed. Unfortunately, some of my friends in the Opposition did not support the passage of that Bill. Now you are saying this.

SHRI BANKA BEHARY DAS: I was in that meeting. I know that some of the Opposition parties opposed it. I know it. But at that time they required the support of two-third majority. Now she does not even require the support of the left parties. She can herself do it because she has got the requisite strength to do it.

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra): Mr. Bhupesh Gupta is devil's advocate.

SHRI BANKA BEHARY DAS: Before I leave this House...

SHRI OM MEHTA: You have forgotten that this House requires a two-thirds majority

SHRI BHUPESH GUPTA: My friend Shri Gorey said that I am devil's advocate. I think it is not very right because devils are sitting to my right. I have never been their advocate, I think. Now, Sir, at this meeting on defections a proposal was made to bring forward a legislation with a view to giving effect to the recommendation, the unanimous recommendation, of the Committee on Defections. Some of us said that the Bill should be brought forward. Unfortunately, I do not know for what reasons my friends sitting to my right opposed it.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: They are angels.

SHRI BHUPESH GUPTA: Very well. I am between the devil and the deep sea. They opposed it. I am sure if they not opposed this, this Bill would have been brought forward. I entirely agree that everything was agreed to Unanimous recommendations should have been implemented. I should ask my friend, Mr. Om Mehta, that a Bill should be brought forward. It is necessary. You take note of it. You immediately take advantage

[Shri Bhupesh Gupta.]

of the situation when everybody is asking for a Bill to be brought forward.

SHRI BANKA BEHARY DAS: Mr. Vice Chairman, if after this debate the Government brings forward such a Bill we will all be happy. But nobody should forget in that meeting also those who opposed are the worst sufferers in this country. But some of those who supported at that time, were also in the Opposition. Therefore, I say when the President mentioned that the politics of manoeuvre had ended, he forgot to speak something about defection. I do not know, perhaps after the Ministries in Gujarat and Mysore have fallen, and, after the S.V.D. Ministry of Bihar has fallen they would be thinking of stopping defections and bringing some measure. My friend, Mr. Mohan Kumaramangalam, is nodding his head. I am very much ashamed to say that the President did not mention such an important aspect which is so vital for the survival of democracy in this country. I thought that after this election the President would think of some electoral reform in this country. Sir, you very well know what amount of expenditure a candidate has to make for getting himself elected. If every Member of the Lok Sabha is asked to speak on oath whether he has conformed to the limit of expenditure that they themselves have passed in the Lok Sabha, they we will have to admit that most of them have violated.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): How much did you spent ?

SHRI BANKA BEHARY DAS: Here I can say on oath when I stood for the Orissa Assembly and got elected, not a single jeep was plying in my constituency. I have not spent more than Rs. 4,000 in my election...

SHRI BHUPESH GUPTA : But the trouble is that every Lok Sabha Member will make the same eloquent speech as you are making.

SHRI BANKA BEHARY DAS: Mr. Bhupesh Gupta should not forget that I was not going to say how much expenditure I incurred. It is Mr. Om Mehta who provoked me to say this.

SHRI MAHAVIR TYAGI: I consider it an act of defection that such a talented person is going to the Assembly.

SHRI BANKA BEHARY DAS: If the Committee on Defections had mentioned that this would amount to defections I would have never gone to the Orissa Assembly. Sir, in view of this mounting expenditure it is high time that some Commission should be set up not only to suggest electoral reform in this country but to think seriously about the expenditure that is involved in an election because now only a rich party and a rich person can have the advantage of elections in this country. The poor party, and the poor man can never get elected to this country, either to the Rajya Sabha or to the Lok Sabha, if something is not done to see that this mounting expenditure is checked and some new method is evolved. Some of my friends of the Congress Party have told me how much money they have got from the Congress sources. I am not going to divulge their names. I am not saying that the Opposition members are angels in this respect. But what I say is, the party which should set the tone to the politics of the country, has itself violated certain norms. So, I think it is high time that the question of electoral reform was considered seriously, and I would have been very happy if the President has mentioned something about it in his Address.

Now, Sir, when the Lok Sabha was dissolved and when Mrs. Indira Gandhi went on the air that night, she spoke about constitutional reforms and about the property right. That was the first Pledge and assurance of Mrs. Gandhi to the people of this country when the Lok Sabha was dissolved. Has that assurance been mentioned in the President's Address? Will Mrs. Gandhi or any of her colleagues who will reply to this debate has the

courage to say that the assurance that was given just after the dissolution of the Lok Sabha about the property right, has been honoured in the President's Address? It has not been honoured. I would have been very happy if the President in his speech had come out forthright saying that the Government was going to amend the Constitution not only to restore the power of Parliament to amend fundamental rights, but also to see that the right to property is removed from the chapter of fundamental rights. The question of constitutional amendment as regards the property right was made an election issue this time. The spokesmen of the "Grand Alliance" said, day in and day out, that the right to property is not only fundamental but sacrosanct. The result is known. The people have thrown their lot on the side of change of fundamental rights to the extent of removing the right to property from the fundamental rights chapter. But the President's Address makes no mention of that. I think Mrs. Gandhi has absolutely forgotten this solemn assurance and promise that was given to the Indian electorate before the elections. I think Mrs. Gandhi should reconsider this and try to accept this challenge that the Indian people have thrown in her face.

Mr. Vice-Chairman, I would say it is high time that a Constitutional Reforms Commission was set up. I am against the demand for a new Constituent Assembly being set up to amend the Constitution. I am not one of those who want the setting up of a new Constituent Assembly because I know that the character of the Constituent Assembly is not going to be different from the character of the new Lok Sabha as the same adult population will be voting for the Constituent Assembly. So, there is no necessity for it. The present Parliament can function as the Constituent Assembly just to amend the Constitution of this country. Now so many issues have been raised. There is the question of Centre-State relations. For some time, the relations may be cordial because the same party will be ruling in the various States. But my friends will not forget that the next elections will be more crucial for them also. So many issues have cropped up during these five years. The question of an Inter-State Council is hanging in the balance. There was a demand from the Indian people, from the Opposition parties in the States, that an Inter-State Council should be set up. To a certain extent there was resistance from the side of the Government of India, but gradually they were succumbing to the idea because they were not having an absolute majority at that time. Now with a two-thirds majority, they may again slip back to their former position; they may think of acting like the Moghuls destined to rule from Delhi. But there is nothing like destiny in the hands of political people. So, I would say that a Constitutional Reforms Commission should be immediately set up to see that the Constitution of this country is changed according to the changing situation and to suit the aspirations of the people of this country.

Mr. Vice-Chairman, I will now refer to the question of the Bangla Desh movement that is going on in East Pakistan. Deliberately I did not participate when Mr. Rajnarain raised this question to-day after the recess. We passed this resolution yesterday. Where is it going to lead us to ? Is more moral support enough for the people of Bangla Desh? See the valiant fight they are conducting against the carnage that was planned when negotiations with Sheikh Mujibur Rahman were going on. Is it the only duty of the Indian people to extend their cooperation and moral support by passing a resolution in this House ? Did we not pass a resolution with more solemnity when the Chinese forces were attacking the northern borders of this country ? At that time the entire Parliament stood up in one voice to support that resolution. But that resolution remained only on paper. When a bitter struggle is going on in a part of this subcontinent, if we want to extend our support, we will have to concretise what type of support we are going to give those brave people. I remember when the Spanish civil war was going on, when the Congress party was just a party and was not in Government, they had given not only moral support, but they had also extended some material

[Shri Banka Behari Das]

support, however meagre it might have been. We also remember those days of China when Dr. Atal went with a mission. That was a non-official mission which went to give support to the Chinese people. But when it comes to East Bengal, when Bangla Desh is in revolt in every street, in every rural area, we are not coming forward to do anything materially. Today afternoon the All-India Radio says that the Pakistani Army, Navy and Air Force, have mounted a counter-attack. And we do not know what will happen there. Bangla Desh may be reduced to just a barren land after some time. Do we satisfy ourselves by passing a resolution in this House? When did our duty when there was a civil war in Spain—at that time we were not in Government, we were under an imperialist rule—when we performed our duty when China was in trouble, I think we have a greater duty to do today when we are an independent country, when we have our own Government. It is in our interest, it is in the interests of the security of this country, that we should give all types of material help to the valiant people who are waging a war against the Colonial regime there. That is why I say we should now recognise the legally constituted Government of Bangla Desh. I will no longer say that it is a provisional Government, because they themselves have stated that it is a legally constituted Government It is high time that the Government of India not only recognised that Government, but tried to influence other friends in this world to recognise that Government. We have already stated that it is very difficult for us just to sit and watch what happens in Bangla Desh. I want that all types of materials help, both madical and food, should be sent to Bengla Desh. We could send it to Spain. We could send it to China. It is very important that the Government of India should have a plan to go to the rescue of the people of Bangla Desh who are fighting their enemy with courage and determination. Without explaining much about it, I want that volunteers should go and halp them. We have instances when volunteers have marched across the borders of their countries to help liberation forces. This is nothing new. The Government of India and the political parties should seriously think about marching their volunteers to support the freedom-fighters in East Pakistan.

In the end I want to say something about the administration of this country. No socialist programme, though there is no mention of a socialist programme in the President's Address, can be implemented without an overall change in the administrative set-up. The bureaucracy is still running supreme in this country. I am reminded today of Lord Curzon, one of the greatest bureaucrates that the imperialist Britain gave birth to. Just after landing in India he had an experience with the bureaucracy that they themselves created in India. He said it was absolutely unsuitable for ruling this country from London.

So, he went back and wrote his famous book in which he said that the administration in India—the dependent India under the colonial rule—suffered from two major defects. One is exorbitant noting and the second is unpardonable delay. I think, after Independence, we still suffer those two maladies. Exorbitant notings are going on whether it is in the Planning Commission or in the Central Ministries and State Departments. The other malady which Lord Curzon referred to, namely, unpardonable delay, is also in existence. Our administration still suffers from it. I think it is high time that some serious thinking is given to change the administrative system in this country. Unless it is changed, no programme, whether it is socialistic, or non-socialistic, can be implemented in this country.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

Mr. Deputy Chairman, in the end I want to say that in order to Establish a new order of society, Whether it is socialist society or any other society, you should have organic relations between your objectives and the organisation. If you say that the Congress Party wants to establish socialism and even if we admit that the

present administration is to reconstruct a society based on socialism, I will say that neither the Congress Party has the requisite qualification to have that organic relation with the government, nor the bureaucratic machinery has that relation with the objectives. . .

SHRI A.D. MANI (Madhya Pradesh): Except the PSP.

SHRI BANKA BEHARY DAS: Shri Mani represents himself and I do not say that PSP also has that capacity. I need not boast like that. But I will say that even those who have two-thirds majority and those who are to accept the challenge in this country and those who have had the good fortune of running the government for the last 25 years have not developed that organic relationship between the party machinery and objectives, and between the bureaucratic machinery and the objectives.

With these words, I thank you, Mr. Deputy Chairman, for giving me this opportunity and I hope that when I go back to my State. . .

SHRI BHUPESH GUPTA: There is a resolution to be discussed tomorrow. And on that you should speak. You go back after that.

SHRI BANKA BEHARY DAS: I hope that in the coming year, even if the President's Address is not amended, it will indicate that the challenge that has been there will be accepted by the Congress Party and Shrimati Indira Gandhi.

SHRIMATI YASHODA REDDY (Andhra Pradesh): We will be sorry to miss him. But we wish him well in Orissa.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI M.S. GURUPADASWAMY): Sir I went through the President's Address carefully and the Address starts; naturally, with a note on election. We are meeting after the mid-term elections. Therefore, it is in the fitness of things that the President starts making reference to the massive support the ruling Congress got recently at the polls. I am not jealous of their victory at all. I am one who will accept the verdict of the electorate. But it should be our concern also to know, to understand the secret, truth and reality of this remarkable success story of the ruling party.

I am not criticizing for the purpose of criticism. But, for all of us, including those who occupy the Treasury Benches, it would be an education and a discovery even, if they make an attempt to understand the reasons for this miracle or this fantastic feat and the phenomenal success achieved by the Ruling Congress. . .

(*Interruption*)

Please don't interrupt me. Sir, the Ruling Congress had all the advantages. The opposition had all the disadvantages. This has got to be understood when dealing with elections. The Prime Minister had the initiative. She decided about the election. She had the advantage of timing. The Opposition parties did not have this advantage at all. My friends have already said that the Prime Minister denied several times that there would be a mid-term poll. But there was the dissolution of the Lok Sabha and then mid-term poll. So she had this advantage of timing. We did not have this advantage.

In addition, she had several other advantageous factors. She had do-linked the Parliamentary election from Assembly elections in most of the States. That gave the advantage to the Prime Minister and her party. She had also had control of the Government machinery with all its power and patronage. Normally, Sir, when Parliament is dissolved, when General Elections are going to be held, the government that is there has to function as a Caretaker Government. It is an accepted convention. But here we find that no such convention was followed. I think during the short period, many, many things were done and many orders were passed Many licences were issued. . . (*Interruption*). You can reply later.

My friend, Shri Akbar Ali Khan, is a very good parliamentarian. I do not think he is ignorant of those things.

[Shri M. S. Gurupadaswamy.]

I only refer to the practices and conventions prevalent in the U.K. In the past also, when there were periodical elections, Mr. Nehru or later when Shrimati Indira Gandhi was heading the Government in 1967, such conventions were observed. They were never flouted. Only this time, Sir, we find that such healthy practices and conventions have been flouted. During this period—between the dissolution of the Lok Sabha and the holding of General Election—the Government used its machinery to its full advantage. And it will be worth having an inquiry into this whether my criticism is true or not. So many benefits have been given to various classes of people during this period—may be, for getting their support in kind or in some other form. Anyway, the fact remains that during this time the governmental machinery was put to the maximum use by the Ruling Party to achieve advantage in the election.

Then, Sir, they had the media of mass communications with them and, as experts in propaganda, used it to their advantage—the radio, the television, the PIB and field publicity agencies. All these agencies and institutions which were under the control of the Government of India were used for their advantage during the election. The parties in opposition have raised this issue several times in Parliament. Even here, I know, there was a demand made that there should be an autonomous corporation for television and the All India Radio. But our friends there did not like this, would not like this. But my point is that the media of mass communication like the radio and television were put into service by the ruling party. Besides, they had the advantage of huge resources. Let us concede that this election was also a battle of resources. In this battle of resources the opposition parties suffered a handicap. They were not able to mobilise resources. Then what? They had the sacred cow and the calf to help them in the election. Then there were all the elements of drama, suspense and surprise.

Sir, you will agree that the election was in the nature of a blitzkrieg. It had all the effects of a blitzkrieg. There was pressure, shock and a lot of manipulation and manoeuvre to create a situation in favour of the ruling party. Over and above all this, and to cap it all, they had a very popular slogan—*Garibi hatao*.

SHRI P.C. MITRA (Bihar): You admit that your slogan was bad.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I admit it. I had been very fair to you.

Sir, it reminds us of some of the historic elections of the past in England. Some election were held on the basis of slogans in Englantd and political parties had won on the hases of mere slogans. The Midlothian campaign of Gladstone was one such election. Later on, Lloyed George won a big victory after the first World War on the basis of slogan. I need not repeat these things, but the fact remains that they had this popular slogan—*Garibi hatao*, in other words quit poverty. And the President has referred to this slogan and has even said "The Central objective of the Government of India, the main theme of the policy, would be to a formulate programmes to eradicate poverty as early as possible."

Poverty cannot be abolished, war on poverty cannot be conducted, cannot be waged, unless and until a net work of anti-poverty programmes, a network of anti-poverty attacks are organised, I want to know whether this document brings out any, such hope to our mind, whether this address has been able to indicate the various activities to wage war against poverty. I do not see such things. My friend very well put it just now that all the schemes that have been adumberated in the President's Address, all the programmes that have been mentioned there were the programmes of last decade. Perhaps in their intoxication of victory they seem to have forgotten that we have begun a new decade, the seventies. We are in the year 1971. The sixties are over but I find now the listing of the programmes and acti-

vities formulated during the last decade. Many of the schemes that have been mentioned here are the schemes formulated by the Planning Commission. What is the departure? There is no departure in fact. As I said this election has been mainly won on the promises, not on the basis of performance and the people have voted, if at all, for this promise but this promise has not been translated into action. There is no indication of such translation in the President's Address. The poverty can be removed, a war on poverty can be waged if there are comprehensive community action programmes. Where are we having these community action programmes. What I find are a few schemes. They have mentioned land reforms. Land reforms have been there. We have to complete the land reforms wherever they are not complete. There is mention of the unemployment problem. In this I must say what has been visualised and what has been sought to be realised is that a few schemes would be formulated and for that purpose Rs. 50 crores have been allotted. Let us understand that poverty cannot be removed and there cannot be elimination of the misery of the people unless and until we create jobs in millions and Rs. 50 crores is a drop in the ocean, and per capita it does not give even a rupee per pair. Rs. 50 crores will be spent on the way side. Unless and until there is a massive programmes for removing unemployment in this country, we cannot make a successful war on poverty. In the Constitution, article 39 is very categorical. It says unless we assure, the people the minimum needs of living, there will be no achievement of social welfare.

The ten-point programme of the Congress has thus included therein that by 1975-76 the Government of India will be fulfilling the minimum needs of the people. I want to know whether that promise is going to be fulfilled at all by 1975-76. That is very closely linked with unemployment. What is the nature of unemployment that is facing us or that is challenging us? There is unemployment in the rural areas. There is en ployment in the urban areas, I say that the Forest affected class is the landless labour in the rural areas. They account for twenty per cent of the rural population. So far, no institution has been organised for this landless class. It is this 20 per cent which has suffered all these twenty-five years of planned development. We have been envisaging that there will be an institution for them, an organisation for them. There should be a land army for organising the landless rural people. They should be trained. They should be educated and their skill should be utilised. Please remember that unless and untill the poor is involved in developmental activities, removal of poverty is not possible. From this point of view we have been saying that a land army has not to be created. The technical know-how has got to be given to them. The surplus manpower in the rural India has got to be utilised for our developmental activities. Developmental chages and a revolution cannot be brought about unless and until we involve the people to bring about transformation and change, but there is no indication of utilising this man-power.

The party to which I belong has envisaged a programme of employment. We have said that a fund of at least a thousand crores has got to be created for this purpose and with a view to mobilising the resources various steps have got to be thought of and taken. I know friends will ask me, Where is the money? How to find thousand crore of rupees? Naturally it is a question that has not to be answered. May I suggest that we may impose an employment tax? We may impose this tax on all the big business and big industries and the plantations. We will be able to collect this amount and we will be able to find the fund for the purpose. May I say that we can go still further and can involve the various people? The institutions are already there like the Panchayats, the community development blocks, etc. Those institutions have got to be involved in the various developmental activities and these will give the necessary instrumentation or the means to organise the various sections of our community. Nothing has been done. How to bring about mass resurgence, how to bring about the mobilisation of resources, is the biggest task in our country.

SHRI BHUPESH GUPTA: I am very much interested in what you have said about the employment tax and I am tempted to support it, but may I say that, when the privy purse abolition Bill comes here, you will also support it?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I was saying that it is necessary to think of raising additional resources to create this fund. I am glad that my friend Shri Bhupesh Gupta is tempted to support me.

SHRI MAHAVIR TYAGI: He is only tempted.

SHRI BHUPESH GUPTA: I said tempted to support because I do not know; if you put employment tax on the big business which I would like, I would like to be assured that Mr. Nijalingappa or Mr. Morarji Desai will not die of heart failure.

SHRI M.S. GURUPADASWAMY : We must also explore the possibility of encouraging the skilled labour, the skilled manpower that we have already in our land, to start their own industries. Very little has been in this respect. We have been saying that our technical men, the engineers, the draftsmen and the rest, are without employment. I think that apart from thinking that the labour should participate in management, both in the public sector and in the private, sector, we should also sponsor industries by these people. Let them run their own industries. All help has to be given to those people who can organise themselves in co-operatives, in firms in partnerships, in companies or as individuals. They must be supported in all their schemes. I commend the idea that we should encourage to organise the skilled manp ower in this country to start their own industries. All the technical financial and managerial assistance has got to be iven by the State.

Next, f say that it is high time we think of fair wages for labour. All these years we have been neglecting this problem. Sir, I am not saying that it is impracticable. It is possible to have fair wages given provided we can plan our strategy of development properly. Without giving fair wages what is the picture we are seeing? There is the high cost of the economy. This is so because the cost of production is very high. The prices are high. In spite of the fact that we are not giving adequate wages the cost of production is soaring. If we rationally distribute our resources and rationally manage our enterprises, I am sure we will be able to give fair wages to our labour. Therefore, I would like the Government to bring before the House schemes to introduce fair wages, to start with at least, in the public sector.

Sir about the public sector many criticisms have been made, but only one thing I would say about it. Even in 1970 these public sector enterprises, which number about 80 or so, have not yielded much result. There is overall deficit; the net loss is Rs. 33 crores. I do not know how this loss can be made up, can be overcome. Various reasons have been advance for such a loss. But the question is whether this Government has got the capacity or the competence to bring about necessary changes so that the public sector may be a beneficial sector hereafter. Today the public sector has become completely servile to the bureaucracy. The bureaucracy has established its despotism over the public sector, but whether it is possible to change its character, whether we can make the public sector industries as an instruments of bringing about social control of the economy, that is the question. Today the whole public sector institutions have been bureaucratic raised and I would very much like that the Government would bring schemes so that these public sector undertakings are streamlined, their management improved, their losses removed, and their progress ensured. As a part of this I may say there is a commitment in the past that the Government would nationalise general insurance. It is one of the points in the ten-point programme.

They have nationalised fourteen banks. I think the same logic holds good in respect of general insurance I think the same thing holds good in respect of foreign banks

also. Why no nationalise these foreign banks and general insurance companies? What prevents them from doing so? And if it is possible for them to have nationalised 14 banks, I think it must be possible for them to nationalise the foreign banks also. It must be equally possible for them to nationalise general insurance.

Sir, the most important thing from the point of view of the people is that they should get the goods of ordinary consumption at a cheaper rate, at a proper price, at a reasonable level. This has been the demand of our people each year. But the prices of commodities are rising every year, even this year. In spite of the Green Revolution, what is it that we are seeing? The prices of commodities which are used by the ordinary people are rising. Mr. Chavan has given some figures about the food prices. He has said in respect of food prices that there is a decline. I do not know whether there is any decline or not. But the general level of prices which consist of food articles and other essential articles has been rising and we have been seeing that over a period of years, since 1960-61 up to now, there has been a rise of 180 per cent in respect of wholesale prices, and a large component of these prices is the price of foodgrains and other essential articles. With a view to bringing about relief to the millions, with a view to giving them some help, some hope, so that they may have an assured living, a living at a less cost, a living which can be possible with limited resources, may I suggest that the wholesale foodgrains trade be socialised? This has been the demand for years. I do not know why this step has not been taken. I am not making out these suggestions with a view to proving my radicalism. No. This has been there in the past. There have been demands that the wholesale foodgrains trade be nationalised. There is no escape from it.

Again, may I point out that there was a Resolution passed at the Nagpur Session of the Congress? They passed that cooperative farming should be accepted, as the main goal to bring about agricultural revolution. What has happened to that Resolution? I know that some cooperative societies have been formed in Maharashtra. The cooperative farming societies that have been formed there have been working very successfully. Even in my State where cooperative societies have been formed for the landed poor in the villages, have been working well. But this has not been followed up elsewhere. I do not think any Government, either the State or the Central Government, has made big efforts to bring about this change. If you start cooperative farming societies in the rural areas, I am sure it will bring about structural change in those areas. With a land army, with the cooperatives, with the Panchayats, with the community development agencies functioning with the cooperation of the whole people there, with a massive programme of employment, with a net work of anti-poverty programmes, I am sure that within a decade we can bring about a radical change and transformation. But I do not see any indication here.

Therefore I started by saying that this Address does not make any departure from the past. It is the usual Address. It is a continuing thing, and there is no for surprise in this. I would have been really happy if the dividends that the ruling party had secured in the elections had been put to proper use.

4 P.M.

They are not putting it, Sir. Now what is happening? In the developmental sector there is a shortfall. Last year there was a shortfall in the developmental expenditure to the extent of Rs. 120 crores. This year, in 1970-71, the shortfall has increased to Rs. 155 crores. They say that they want to have more and more employment. How can there be employment without expansion of productive activities in the country, when the developmental expenditure is at a low key, when there is no increase in investment at all?

Besides, productive capacities are not being fully utilised in the various sectors. Scarcity is operating in every sector. There is in the near future going to be scarcity in the petroleum products. There is going

[Shri M. S. Gurupadaswamy.]

to be scarcity in aluminium. There is already scarcity in respect of fertilisers and steel. Various other scarcities are operating already in the economy. On the other hand, there is neutralised capacity. It is said that nearly 30 per cent. of the industrial capacity is neutralised for various reasons. Therefore, the economy is bleak with scarcity. There is financial instability because there is price rise. There is economic instability because there are scarcities operating and we are saying that now we want to create employment potential more and more with Rs. 50 crores.

They call it a crash programme. I do not know whether it is a crash programme or a trash programme. With Rs. 50 crores how can you create a crash programme? With this money how can you create a huge employment potential which is necessary? What will happen to the back log of unemployment? Therefore, it is very necessary to have a sound industrial programme. I am afraid with the shortfall in expenditure and investment, the objectives, the targets that have been envisaged in the Plan are not being realised. On the contrary, we have been diverting funds towards various fantastic schemes. Target investments in the plan are not realised. There is diversion of funds diversion of materials for various other things. I am not sure whether the targets envisaged there also will be realised.

Sir, I charge this Government of terrible mismanagement in the economy, misapplication of funds, misdirection of resources as a result of which we have been facing a crisis. There is crisis in the sector of prices. There is crisis in the sector of wages. There is crisis in the sector of employment. There is crisis in the sector of production, and there is crisis in the sector of credit also. I am not sure whether the Government has been thinking of having an integrated approach to resolve these problems. I would have expected even late as this that the Government would have a rational price, income and wage policy. I do not think they are following any policy in respect of wages, prices or income. All these things should be integrated. I suggest, Sir, the Government even now should consider to have a rational wage policy, a rational income policy and a rational price policy. Until and unless this is done it is very difficult to resolve the basic contradictions operating in the economy.

Today disparities are increasing; they are ever-increasing during these last five years of the present Prime Minister's rule. I am sorry to say that during this period of progressive rule the disparities of income between the rich and the poor have been increasing. This is a fact. There is no equalisation. If you want to bring about socialism, the most important aspect of socialism is to bring about equalisation, equalisation of consumption, equalisation of incomes, equalisation of wealth. On the contrary, what do I see? In spite of the fact that they are committed to socialism, I find the monopolist getting more and more licences, more and more patronage, and so on. In the last few months it is known to all people that it is the monopoly capital which is having the maximum benefit of this economy.

The net result has been that the money that is available is going to their pockets. Sir, it is very interesting to note that the major portion of the advances made by the 14 nationalised banks since their nationalisation is going to the capitalist class. It is not going to the craftsmen, the poor people, the rickshaw-pullers, the tonga-drivers or the taxiwallahs. The major portion is still going to the capitalist class. That creates difficulties and that brings about various disparities and distortions in our economy. To-day the economy is not stable. It is threatened with instability because of various things I have said. But there seems to be white-washing going on. If the Government is really sincere in bringing about social change and social justice in the country, it should evolve schemes for the bottom class, for the poorer class of our society. Their

per capita income has been going down year after year. I would be happy if the Government brings forward schemes and projects to alleviate the sufferings of these people, involve them in developmental activities and give them jobs and make them contribute to production, instead of keeping them only on the basis of promises. Sir, the President's Address should have been an Address made on the basis of performance But it is only an Address made on the basis of promises. I am not sure whether these promises will be fulfilled, whether poverty will be abolished. But may I say that when you bring forward radical measures, progressive measures, I would like to support them. My party is committed to such things. My friend just now asked me, "What will you do when the privy purses abolition Bill comes?" You must wait and see. Why should you raise this question just now? Let the Bill come and you will know our attitude at the right time. But let me assure him and others that our party is committed to socialism and socialist change. We would like the ruling party and others here to be co-sharers and participate in the drama of economic transformation of the country. I assure them that our party will not lag behind, particularly I will not lag behind, to support such progressive measures. With these words, I conclude.

SHRI P. C. MITRA: Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to support the Motion of thanks, moved by Shrimati Purabi Mukherjee, to the President for his Address to both Houses of Parliament on the 23rd March.

I heard just now with full attention the speech of the Leader of the Opposition. I am happy that he is having introspection and is returning to his socialist ideas. He has given a few concrete suggestions and I would ask the Government to consider those suggestions, particularly the tax on employment. He has also given an assurance that all progressive measures will be supported by them. This indicates that the Alliance is no more there and they are breaking off from the Alliance and trying to be in line with the progressive ideas of the country. I am happy that this change has come so soon. He has also admitted that their slogan of "Indira Hatao" has failed and it was a wrong one, and that the "Garibi Hatao" programme created hope in the people and on that, the people voted *en masse* for the Congress. One thing I must tell him, it was not a slogan, it was a programme. And all the details of the programme cannot be expected to be contained in the President's Address. The President has already mentioned that theirs is a massive mandate for a peaceful change that must swiftly and visibly alter the picture of poverty and alienation in our land. My friend, Mr. Banka Behary Das, said that, there is not a word of socialism in the whole Address. Yes, but the word "Socialism" need not necessarily be used. What we want to do or bring about is socialism. I would draw his attention to para 4 where the President says—

> "My Government have been returned to office on the clear pledge that the central objective of our policy must be the abolition of poverty. To achieve this, my Government are firmly committed to implementing the economic and social transformation outlined in the manifesto which has received such overwhelming support of the electorate."

Therefore, if the word "Socialism" has not been used in the Address, it does not matter. He has actually mentioned about the social transformation outlined in the manifesto and that they are committed to implementing it . . .

SHRI BANKA BEHARY DAS: Can you tell me what the transformation is that has been mentioned in the President's Address?

SHRI P. C. MITRA: It is only an outline. The President has rightly observed that the people have given a clear indication as to what they want. They have reposed complete confidence in the leadership of our Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, who has clearly spelt out before the people what programmes she wants to follow.

[Shri P. C. Mitra]

What is the main programme before the country? That disparities in income and wealth will be reduced to the minimum, that the people will be provided with their minimum needs. And, as the Leader of the Opposition has just now said, only by passing a resolution you cannot abolish poverty. You have to work hard. The people and the Government will have to work hard for achieving that end...

SHRI MAHAVIR TYAGI: Is there any precise programme for which we have to work hard because poverty cannot be eliminated by passing an Act? Suppose we pass an Act, Antipoverty Act, will poverty go?

SHRI P. C. MITRA : No, it will not. But the Finance Minister has indicated that in the Budget that will follow, some indications will be there. Now actually the President's Address was delivered hardly ten days after the announcement of the results of the election and, therefore, one should not expect that everything would be contained in that Address. Incidentally, I cannot refrain from referring to...

श्री मान सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : गरीबी को दूर करने के लिए कितना समय चाहिए, इस को जरा बता सकेंगे। पांच साल, दस साल, कितना समय लगेगा ?

श्री प्रतुल चन्द्र मित्र : समय लगेगा इसीलिए हमने नहीं कहा है कि यह एक वर्ष में या दो वर्ष में खत्म हो जाएगी। इस में समय लगेगा यह सभी को मालूम है और इसलिए नहीं कहा गया है कि हम इस को एक वर्ष में खत्म कर देंगे।

Incidentally, I cannot refrain from referring to the happenings just in the neighbouring country where similar elections were held in December, 1970. The people *en masse* voted for certain programmes one of which was complete autonomy for East Bengal which they have now named as Bangla Desh. After the elections President Yahya Khan said that the aspirations of the electorate, the expectations of the electorate, would be fulfilled. President Yahya Khan actually said that Sheikh Mujibur Rehman will be the Prime Minister of Pakistan. But what has he done now? But what was the outcome? Mr. Yahya Khan somehow continued his talks with Mr. Mujibur Rehman only to deceive the people of East Bengal and now he is ruthlessly suppressing them with military force.

We passed a resolution yesterday and that has been well received by everybody. In the resolution we said that we extend our full support and sympathy for the people of East Bengal in their struggle for independence from the colonial West Pakistan government. But that is not enough. We must recognise the government of Bangla Desh. They have declared their independence. Even Mr. Yahya Khan said in his broadcast that for 21 days Mr. Mujibur Rehman's government was continuing in Bangla Desh. They have their own flag. The Pakistani flag was lowered and dishonoured and Bangla Desh flag was unfurled. That was done in his presence. Thus Bangla Desh actually became independent. Later on, Mr. Yahya Khan went away and ordered his army to suppress the people of Bangla Desh with brute force. When we passed a resolution of sympathy and support to Bangla Desh, every kind of material support should also be sent to them. I endorse the view of Shri Banka Behary Das that we should recognise the Government of Bangla Desh and see that voluntary forces go from here to help those people. We have already seen that many other countries sending volunteers during the Spanish Civil War.

The President was pleased to observe that for higher production, some procedure should be evolved in consultation with trade union leaders so that there will be better industrial relations and the workers may feel that the respective industries are their own. But the attitude that is evident in the managements of the public sector

undertakings towards workers is not ideal. We find that they have no sympathy for their workers. There is thus no difference between the attitude of managements of public sector undertakings and private sector companies. I will quote an incident in the Heavy Engineering Corporation at Ranchi. There was a notice for strike by 700 diploma holders and junior engineers. It was to start on the 15th January The then Minister of State of Heavy Engineering and Steel, Shri Mohd. Qureshi had gone there. He tried for some settlement and asked me to intervene in the matter. The management agreed to talk with me. The workers wanted the management to withdraw the suspension orders and charge-sheets. The management agreed to withdraw the suspension orders, but not the charge-sheets. The difference between the two parties was only very minor and on this small issue the strike continued for about 40 days. Ultimately, before the arrival of the Prime Minister at Ranchi, the management accepted that.

The strike was withdrawn. But till midnight before the 15th January I had been there and I persuaded the workers not to go on strike if the suspension orders were withdrawn. And they agreed to it. But the management said that the suspension orders would be withdrawn but the charge-sheets would remain. That indicated that they only wanted to teach a lesson to the employees and they have no sympathy for them, and therefore, I will ask the Government first to. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI P. C. MITRA: Regarding the trend of price I would like to say something. Just on the eve of elections there was a spurt in prices of cloth and kerosene in Bihar. Kerosene was selling at about Rs. 2 per litre instead of 60 paise per litre. And this continued till the end of election. When I raised the matter with the District Magistrate, he said, "Yes, after the election I will look into the matter". In the same way, the cloth prices also went on. Even the Prime Minister declared openly that there should be an inquiry as to how the prices of cloth had risen so much. But I do not know whether there has been any inquiry ordered by the State Government or the Centre set up an inquiry committee or commission to inquire into the matter . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI P. C. MITRA: Some profiteers actually made profits and they enjoyed these profits. Sir, the distributors of kerosene should be made responsible for maintenance of its prices. These things can be controlled . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI P. C. MITRA: It is only after people suffer much the authorities try to rectify the maladies.

Thank you.

SHRI A. K. A. ABDULSAMAD (Tamil Nadu) : Mr. Deputy Chairman, Sir, I am glad to note that this year's President's address was with a clear objective—the objective of abolition of poverty. Sir, it was a sad reflection on our past administration that this poverty was not eradicated even after 25 years of our Independence. Now, the common people sincerely believe that there is going to be a concerted effort to uplift the downtrodden people. This hope is amply reflected in the massive victory of the ruling party. For the first time in the history of our country, the ruling party has got not only majority of seats in the Parliament but also majority of votes from the people. The recent election is a historic one in the sense it has heralded an era of political stability and strength. Therefore, the Government must hasten to fulfil the aspirations of the people within the short space of time. They expect some quick results. They would not tolerate any more any tall-talk of Socialism. They want socialism in practice.

Sir, this election has brought forward many salient features to the forefront. For the first time after Independence, the

[Shri A. K. A. Abdulsamad.]

importance of the Muslim voters has been felt by almost every political party in the country. In more than 150 parliamentary constituencies, the Muslims are the deciding factor. Now they have voted *en-masse* for a stable non-communal and secular Government with the hope that an earnest attempt would be made to redress their real grievances. I hope this important factor has been taken note by the Government headed by Indiraji.

The Muslims are not asking for privileges. But what they want is honourable existence and equal opportunity.

They should not be treated as second-rate citizens any more. The Muslim youths should not be prevented from taking legitimate positions, simply because they happen to be Muslims. I hope and trust that this Government will give due consideration to the legitimate demands of the Muslims of the country.

Sir, I want to remind this party in power that it is already committed to the Muslims, through its election pledges, for the protection of minorities, rights, specially with regard to educational institutions, both established by them and those established for them at their instance.

The Ruling Congress Election Manifesto made the following to the people:

> "The Congress will strive to ensure that the minorities have full freedom to establish, manage and run educational and other institutions. The Congress will strive to ensure the democratic functioning and protect the autonomous character of educational institutions including those established at the instance of, and for the benefit of the minorities."

In this background, Sir, I was surprised to see that nothing was mentioned in the President's Address about the restoration of Aligarh Muslim University on its original basis and giving due recognition to the sweet language of Urdu. I hope and trust that necessary legislation would be brought before the House during the next Session.

I am happy to note that President had condemned violence and communal tension and reiterated the Government's determination to eliminate the politics of murder and assault.

Sir, in this connection, special mention must be made with regard to what had happened in Moradabad and Aligarh. I accuse the fallen S. V. D. Government for its inefficiency in dealing with the situation and even its connivance with the goondas. Sir, in Moradabad, even after the polling, a reign of terror was let loose on the innocent and helpless Muslims and the police committed atrocities upon the minority community. Every Muslim Mohalla was raided by this police force, and most respected and innocent people were mercilessly beaten-up. I want that the Government should set up judicial Committee to go into all aspects of the matter. Now the S.V.D. Government had met with its own doom. Let the new Government take the question of punishing the guilty and rendering necessary help to the affected people.

Sir, I welcome the crash scheme for rural employment. It has rightly envisaged that the schemes be linked with those of raising the productivity of agriculture.

Sir, this scheme as well may be linked up with the schemes of connecting Ganges and Cauvery. I think this is the most opportune time to take up this gigantic project which would really unite the country and give employment to hundreds of thousands of people.

Sir, our President has rightly referred about the intolerable living conditions of the urban poor. It is really a pathetic sight to witness the life of not only the slum dwellers, but also the street dwellers. In the words of Goldsmith, "Their wretchedness excites horror rather than pity." In the city of Madras one tenth of the population live in the streets. I want to suggest

that due priority must be given for constructing sleeping houses in various quarters of the cities for the benefit of street dwellers.

श्री मोहम्मद उस्मान (राजस्थान) : मोहतरम डिपुटी चेयरमैन साहब, मैं इस मोशन आफ थैंक्स की हरफ-ब-हरफ ताईद करता हूँ जो सदर जम्हूरिया के खुतवाये सदारत के लिए पेश किया गया है। मै तहे दिल से सदर जम्हूरिया के खुतवा सदारत का इस्तकबाल करता हूँ जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की तरफ से उन तमाम वादों को पूरा करने का यकीन दिलाया है जो हमारी जमात ने इलेक्शन मेनीफेस्टो के जरिए हिन्दुस्तान के करोड़ों अवाम से किये थे।

मोहतरम डिपुटी चेयरमैन साहब, हालिया चुनाव के नतीजे बड़े तारीख-साज़ बड़े इबरतनाक और बड़े आजमाईशी और इम्तिहान में डालने वाले हैं। तारीखी इम्तिहाज़ से कि चुनाव लड़ने वालों में एक तबका उन दकियानूसी रजअतपसन्दों, राजा-महाराजाओं, पूंजीपतियों और मजहबी मजनूनों का मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर वोट हासिल करने के लिए मैदान में आया था जो हिन्दुस्तान को सदियों पीछे की तरफ ले जाने वाला था। कहने को उन्होंने भी सही कहा कि वह हिन्दुस्तान की तकदीर बना देंगे, अवाम की तकलीफें और दुख-दरद दूर कर देंगे।

दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सेक्यूलरिजम, जम्हूरियत, समाजवाद और अहिंसा के असूलों के साथ वोट की तालिब हुई। जनता ने तहे दिल से पूरे जोरो-खरोश और एतमाद के साथ हमारी जमात का साथ दिया और उसको शानदार कामयाबी अता की, गोया कि उसने तारीख के एक नए दौर, नई करवट, नए इन्कलाब का इस्तकबाल किया, जो हिन्दुस्तान को समाजवाद की तरफ ले जाने वाला है। मैंने इस माने में हालिया चुनावों के नतीजों को तारीखसाज़ कहा है। यह नतायज उन लोगों के लिए बड़े इबरतनाक हैं, सबकनआमोज़ हैं और आँखें खोल देने वाले हैं, जो हिन्दुस्तान के पोलिटिकल जाइन्ट्स कहलाए जाते थे वह अपनी उमरों के इब्तिदाई और दरमियागी हिस्सों में तूफानोतलातुम से खेलते हुए हमारे साथ साथ हमसफर थे, मगर साहिल पर पहुंचते पहुंचते वादे मुखालिफ की रौ में बह गए और डूब गए। हिन्दुस्तान के करोड़ों आवाम ने यह फैसला दे दिया है कि आज की दुनियां में सरमायापरस्ती, फिरकापरस्ती, मजहबी जुनून और तास्सुब ततबुद ऊंचनीच और अदम मसावात की कोई गुजाइश नहीं। अफसोस वह बड़ी बड़ी सियासी तोपें जो इन असूलों की मुहाफिज़त करने वाली थीं वह गांव के बनाए हुए खोखे साबित हुई और जनता की ताकत के सामने बेकार हो कर रह गई।

मोहतरम डिपुटी चेयरमेन साहब, जैसा कि मैंने अर्ज किया है, हालिया चुनाव के नतायज बड़े आजमायशी और इम्तिहान में डालने वाले भी है। जनता ने हमें जितनी शानदार कामयाबी से नवाजा है हमारी जिम्मेदारियां उतनी ही ज्यादा बढ़ गई हैं। इसमें शक नही कि हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा मोहतरिमा इन्दिरा गांधी ने हमारी सही कयादत और रहनुमाई की है और हिन्दुस्तान के करोड़ो इनसानों की परेशानी और दुख दर्द को समझा है। उन्होंने शिद्दत से यह महसूस किया है कि एक तरफ चन्द लोग हिन्दुस्तान की तमाम दौलत समेटे हुए जिन्दगी की तमाम खुशियों, राहतों,

[श्री मोहम्मद उस्मान]

एशोआराम और आशाइस के ठेकेदार, जागीरदार और वारिस बने हुए है और दूसरी तरफ करोड़ों गरीब, मजदूर, किसान और अवाम इफिलास और गरीबी मे जिन्दगी और मौत की कशमश में मुबतिला हैं। उन्हें पेट भर खाना मय्यसर नहीं कही, सर घुसाने को जगह नहीं, तन ढांपने को कपड़ा नहीं। आखिर यह सब किस जुर्म की पादाश में, हिन्दुस्तान के नागरिक और इनसान होने के नाते उनके साथ यह नाइन्साफी क्यों ? जब हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने आवाम की मुश्किलात का अहसास किया, उनके जज़बात, एहसासात और उमंगों का खैरमकदम दिया और उनकी जरूरियातें, मईशत को पूरा करने का बीड़ा उठाया तो जनता ने दिल खोल कर अपने खलूस, एतमाद और एहतराम के खजाने प्राइम मिनिस्टर साहिब के कदमों पर लुटा दिए। ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान एक बहुत बड़े इनकलाबी दौर में कदम रख चुका है, ऐसा इनकलाबी दौर जिसकी रफ्तार तूफान और आंधी की मानिंद है। जनता ने तूफानी रफ्तार और जोशोखरोश से वोट दिए हैं। किसलिए ? गरीबी मिटाने के लिए, राजाओं-महाराजाओं के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार खत्म करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, समाज के घिनाउने और रसते हुए नासूर पूजीपतियों को आम इनसान की सतह पर लाने के लिए, उनकी करोड़ो और अरबों रुपयों की जायदादो पर हद कायम करने के लिए, भूमि सुधार के लिए, गरीबों-मजदूरों, किसानो के लिए, शहरों और गावों में रहने बसने, खाने पीने और खुशहाल जिन्दगी बसर करने के साधन जुटाने के लिए, हिन्दुस्तान की तालीमी, सनाती, तिजारती, माशरती, तहजीबी, तपुद्दनी, सफाकती और रूहानी तरक्की के लिए दुनियां में सच्चाई, अहिंसा और आलाइनसानी कदरों का बोलबाला करने के लिए, जिसके लिए हिन्दुस्तान को हमेशा नाज रहा है और रहेगा। मुझे इन्तिहाई खुशी है कि सदर जम्हूरिया ने अपने खुतबे सदारत में हमारी सरकार की तरफ से उन तमाम बातों और वादों के पूरा करने की तरफ कदम उठाने और उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश करने का यकीन दिलाया है। मुझे इस बात का अहसास है और बहुत शिद्दत के साथ अहसास है कि वादा करना आसान है लेकिन उसका पूरा करना बहुत मुश्किल है।

'गुज़रो मंजिल तस्लीमो रज़ा मुश्किल है,
वादा आसान है, वादे की बफा मुश्किल है।'

ऊपर बयान किए हुए बहुत से वादे ऐसे हैं जो वयककलम, फौरी तौर पर पूरे किए जा सकते हैं और बहुत से ऐसे है जिनके पूरा करने में वक्त, मेहनत, परिश्रम और लगन की जरूरत है। बेरोज़गारी और अशियाए खुर्द नौश की मंहगाई के मसायल हमारी फौरी नवज्जह के मुहताज हैं। मेरे ख्याल में ही नहीं, इस तमाम हाउस के ख्याल में और तमाम हाउस के ख्याल में ही नहीं, हिन्दुस्तान के करोड़ो इनसानों के ख्याल में प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों का खात्मा, रूरल और अर्बन प्रापर्टी पर हदबन्दी, फारेन बैंकस का नैशनलाइजेशन और फिरकावाराना फसादात की रोक-थाम के लिए कानून बना देना या मौजूदा कानून और दस्तूर में तरमीम व तन्सीख कर इन मसायल को हल करने में सरकार को कोई दिक्कत और रुकावट नही है।

आखिर में मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि हमें अजमो हिम्मत और हौसले से काम ले कर इस इम्तेहान में कामयाब होना है। मुखालिफ हमारे लिये मुश्किलात पैदा करेंगे मगर हमें उम्मीद है कि हम अपनी प्राइम मिनिस्टर साहिबा की काबिलाना रहनुमाई में चले जायेंगे हंसते खेलते तूफान की मौजों में अगर आसानियां हों जिन्दगी दुश्वार हो जाये।

आखिर मे मैं चन्द अल्फाज़ बगला देश के सिलसिले में अर्ज़ करूगा। बगला देश के लोगों ने जो अपनी आज़ादी की तहरीफ के लिये ज़दोज़हद की और आइनी तौर पर एलेक्शन लड़ कर जो पब्लिक का मेन्डेट हासिल किया उसको जिस बुरी तरह से कुचला जा रहा है और निहत्थे लोगों पर जिस तरह से बर्बरता और ज़ालिमाना अन्दाज से पाकिस्तान की गर्वनमेंट जुल्म कर रही है वह किसी तरह से काबिले बर्दाश्त नहीं।

पाकिस्तान की गर्वनमेंट मज़हबी बुनियाद पर कायम है और उनको दावा है कि वे इस्लाम के अलमबरदार हैं। वे एक इस्लामी हुकूमत का दावा करते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस्लाम ने कभी इस किस्म के मजालिम, इस किस्म की बर्बरियत की इजाज़त नहीं दी। इस्लाम असल में दुनियां में पीस और सलामती चाहता है। इस्लाम दुनियां में अमन चाहता है। लेकिन पाकिस्तान की गर्वनमेंट ने अपने मौजूदा अमल से यह साबित किया के उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी हुकूमत जबर और मज़ालिम पर उतरी हुई है। मैं समझता हूँ कि हमारी गर्वनमेंट ने जो बंगला देश के लोगों के लिए हमदर्दी का रिज़ोल्यूशन पास किया और जिन खयालात का इज़हार किया वे अपनी जगह पर मुनासिब है, लेकिन महज़ जबानी हमदर्दी से कुछ नहीं होता जब तक कि हम कोई अमली कदम उनके लिये नहीं उठायेंगे। हम अपनी ज़बानी बातों से किसी के सामने अपने आप को सही तौर पर उनका हमदर्द साबित नहीं कर सकेंगे। हिन्दुस्तान के आवाम की हमदर्दियां जो बगला देश के लोगों के लिये है उनका साथ देते हुए हमारी गर्वनमेंट को कोई ऐसा अमली कदम उठाना चाहिये कि वह पाकिस्तान की मिलिट्री के मजालिम से बच सके और उनकी आजादी का हक तसलीम किया जाए।

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: Mr. Deputy Chairman, Sir, I would have been glad if I could join the Motion of Thanks without regrets but my regret is that the Address makes no reference to the heroic struggle of the people of Bangla Desh (East Bengal) for securing human rights and against despotic military rule. My regret is that the Address makes no reference to the urgency of granting unemployment allowance or subsidy to the unemployed. My regret is that the Address makes no reference to the need for recasting the Fourth Five Year Plan to arrest the rise in prices of essential commodities of life and curb monopoly. I shall deal with the last two items of my amendments if time permits. Now it is admitted on all sides that unemployment and the spiralling rise in prices are the two manacing itmes in our socal life.

Now it is said that unemployment will be solved. It is a promise. It is there in the Constitution also. But what has been done? Till that is done, the test lies in the fact that the Government assures about subsistence allowance for the unemployed.

About rise in prices, thanks to Dr. Ram Manohar Lohia, it was he who started a movement for holding the price line, but the price line has not been held. The price line has gone up higher and higher. What are we going to do? We do not know that. Nobody has spoken

[Shri Dwijendra Lal Sen Gupta]

anything about that. Anyway that is not the point for which I would like to waste my time.

Mr. Deputy Chairman, my friends have confused the resolution of yesterday with the speech of the President. My amendments are all in regard to the speech of the President. Paragraphs 20 to 22 of the President's speech deal with the country's foreign affairs. Paragraph 21 says:

> "The situation in Indo-China has deteriorated further. Ever widening areas are engulfed in war embracing Cambodia and Laos."

Why on the 23rd of March this speech did not mention anything about East Bengal, which it should have? I shall not make any regret for that because, though late, the Prime Minister moved the resolution yesterday and the House accepted that. But what about that ? I find paragraph 5 of the resolution of yesterday says:

> "Bearing in mind the permanent interest which India has in peace, and committed as we are to uphold and defend human rights", etc.

Where was this sense of human rights till yesterday? I come from East Bengal. I have sympathy with my neighbouring State and I have greater sympathy because the question of human rights is involved here, because it is a war of the people against the despotic military rule. Therefore, democratic rights are involved here.

I shall now give this House certain figures which are alarming. Now 56 per cent of the total population of Pakistan is from East Bengal, but from Quaid-e-Azam Jinnah to the rest what they say? Urdu should be the language of the Government, or in other words the language of 44 per cent shall be the language for the 100 per cent. You know that on 21st February, 1956, the people of East Bengal had to give their blood in defence of their language and they made their movement for Bengali being the national language and that day is observed as 'Bengalee Language Day', 'Martyrs' Day'.

Mr. Deputy Chairman, I am giving this House certain figures to show why the people of East Bengal rose in revolt, why Mujibur Rahman has declared an independent East Bengal. There are the figures. Revenue expenditure for East Bengal is Rs. 1500 crores, whereas revenue expenditure for West Pakistan is Rs. 5000 crores. Development expenditure for East Bengal is Rs. 3000 crores; for West Pakistan it is Rs. 6000 crores. In regard to foreign aid only 20 per cent is given to East Bengal and 80 per cent goes to West Pakistan. As regards imports of foreign goods only 25 per cent comes to East Bengal and 75 per cent goes to West Pakistan. As regards Central Services 15 per cent is from East Bengal and 85 per cent is from West Pakistan. As regards Armed Forces only 10 per cent is from East Bengal and 90 per cent is from West Pakistan. This is about the dominating position of West Pakistan.

With regard to commodities, rice is sold in East Bengal at Rs. 50 per maund, whereas it is sold at Rs. 25 per maund in West Pakistan. Mustard oil, it is Rs. 5 per seer in East Bengal and Rs. 2.5 in West Pakistan. Gold, which is an international commodity, is Rs. 170 per tola in East Bengal and Rs. 130 in West Pakistan.

Now, this is the position. Can anybody, far less the militant and revolutionary Bengalees, tolerate it?

As against this, there was a demand for the restoration of the democratic constitution. There was voting for the National Assembly; 160 was the strength of the Awami League led by Sheikh Mujibur Rahman as against the total of 300. There was the promise of a new National Assembly. But it was deferred without consulting Sheikh Mujibur Rahman, the leader of the main party. Now what do you see? There was a clandestine conspiracy, I should say. I am reading from newspaper cuttings. This is the news which appeared on 17-3-1971:

"Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman, has asked the people of Bangla Desh to obey the directives of his compan on 'if you do not find me in your midst during the movement for the realisation of the people's rights'."

Mr. Rahman made this indirect reference to a horrible threat to his life in a recent public meeting, according to the Pakistan Press International. Why has he said that? He says it on the 16th March. On that same day, talks between Gen. Yahya Khan and Sheikh Mujibur Rahman began. And he scented that there might be foul play. He is the leader of 7.5 crores of Bengalees there. Gen. Yahya Khan took time made all his military preparations, and he declared war. You know that Gen. Tikka Khan was the Governor-designate in East Pakistan. But even the High Court Judge did not agree to swear him for Governorship and cooks refused to cook for him From the High Court Judge down to he common man, everybody was behind Sheikh Mujibur Rahman.

I will give you some statistics of as regards military strength. Sheikh Mujibur Rahman's freedom fighters have with them the Eastern Provincial. Rifle consisting of 18,000 men the Eastern Bengal Rifle consisting only of 6000 men and the police with 30,000 men, as against Gen. Yahya's Khan's strength of Army of 70,000, tanks 16 and with planes innumerable. What is our task? Our task is not to wait but to immediately declare on democratic principle that we recognise the Bangla Desh Governme it led by Sheikh Mujibur Rahman as an independent country in the comity of nations. That is a new nation born, that is a new independent country born, and India, consistent with its tradition, should recognise it.

Now, Mr. Deputy Chairman, you will find the horror there. More than three lakhs of men have been killed by them: I should say, they have been butchered. It is a case of genocide. I read from a newspaper of 31st March, datelined Agartala—

"Sheikh Kamal, the eldest son of Sheikh Mujibur Rahman, was crushed to death in Dacca under a tank on March 26, a top Awami League leader told a UNI correspondent on the Indo-Pakistan border.

"Sheikh Kamal, a post-graduate student of Dacca University, was sleeping in his house at Dhanmandi when a tank attack was made."

The same paper says

"Fates of girl students unkown.

"All the resident girl students of Dacca University are missing, revolutionary sources from across the border reported today.

"They said the male students were with the Bangla Desh freedom fighting forces but the girls living in the hostels were not traceable.

"Their fate is unknown to the Government of Free Bengal, they said."

Then I find this news item in another paper that 50 scholars were shot dead.

Now, Mr. Deputy Chairman, is there any time for us to brook or to pause over the matter? Should we only pass a Resolution, an innocuous Resolution, as we passed yesterday? We have expressed our sentiments there. But is it time for expressing sentiment? It is time for action. If we mean business, if we want to live in peace, it is our bounden duty to take up the cause of the East Bengal people as our own.

If there is unrest and military oppression by these West Pakistan people, then there would be exodus. Our economy will suffer badly. Apart from that, out of the 7.5 crores of people in East Bengal, one crore are minorities about whom we are pledge bound. Forget everything else.

Sir, our Ambassador, Mr. Samar Sen, has talked with the U.S. Government. We have talked to the Russian Government. By all means do it. But should we not do something more? Is it time for negotiations

[Shri Dwijendra Lal Sen Gupta]

only? How long would these people stand this type of oppression? So, Mr. Deputy Chairman, through you I appeal to the Government of India to take a realistic attitude and go ahead without communication, moral or otherwise. Our cause is great. Whatever we have promised we should do. There should be no double dealing, no double standards.

श्रीमती प्रतिभा सिंह (बिहार) : उप-सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ बातों की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में पहली बात जिस पर जोर दिया है वह कृषि उत्पादन के संबंध में है। उन्होंने कहा है कि भूमि सुधार के संबंध में कुछ योजनाएं लेंगे, जिसमें सबसे पहली, सीलिंग अर्थात जोत की अधिकतम सीमा कम करने की बात, उन्होंने रखी है। जब आप सीलिंग की बात उठाते हैं, तो कुछ राज्यों में विशेष परिस्थिति है जिसको बिना सुधारे हुए सीलिंग के कोई मानी नहीं होते हैं। खास करके, बिहार के संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि जब आप सीमा की पाबंदी लाते हैं तो उसके साथ साथ आपको कांसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज की बात भी उठानी पड़ेगी। बिना कांसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज के जोत की सीमा कम करने के द्वारा भूमि सुधार की जो बात आप करना चाहते हैं, और उसके द्वारा जो अन्न का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं वह सम्भव नहीं हो सकता है क्योंकि गहन खेती की प्रक्रिया फैली हुई जगहों की जमीन पर कार्यान्वित होना कठिन है। भूमि सुधार के सिलसिले में अगर आप 15 बीघा जमीन या 10 बीघा जमीन सीलिंग उतारें—25 बीघा ले, 30 बीघा लें—अगर वह पांच, सात गांवों में अलग अलग है तो किसान किस तरह से वहां काम कर सकता है। उसको अगर सरकारी कर्ज मिलता है, वह नल-कूप वहां लगाना चाहता है तो उसके लिए यह बात सम्भव नहीं है। इसलिए जब भी सरकार कोई कार्य करना चाहती है कानून के द्वारा तो उसमें उसकी प्रक्रिया करने का समय उस कानून के लागू होने पर उसके फल (Result) से सम्बन्धित, बाकी भी जितनी डीटेल्स हैं, उन सबके विषय में सरकार का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए।

एक दूसरी चीज भी है, जिसके संबंध में दो तीन सवाल पैदा होते हैं। आप जब सिलिंग करते हैं, तो जो बड़े किसान हैं, उनकी जो अधिक जमीन है, वह आपको प्राप्त होती है। तो आप उस प्राप्त जमीन के बंटवारे का क्या सिलसिला करते हैं क्योंकि हम लोगों ने तजुर्बे से देखा है कि भूदान में जो जमीन सरकार के पास आई उसके बांट में इसलिए सरकार को सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, क्योंकि एक तो भूदान में जिन लोगों ने भी जमीन दी, सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया कि वह जमीन सड़क की थी, कुंओं की थी, तालाब की थी, सूखी पड़ी हुई जमीन थी या बिलकुल बेकार की जमीन थी और कागजों में वह जमीन लाखों एकड़ की थी इसलिए उसके बंटवारे का कोई हिसाब किताब आज तक नहीं हो सका। और जितना खर्चा भूदान के कामों में हुआ तो उस सिलसिले में गरीब हरिजनों को और गरीब पिछड़ी जातियों के किसानों को जो कुछ मदद मिल सकती थी वह नहीं मिल सकी।

उपसभापति महोदय, इस बात को मैंने देखा तो मैंने सोचा कि आपके द्वारा सरकार के सामने इस बात को लाऊं और जो लोग भी इन चीजों को पूरी तरह से

कार्यान्वित करने का भार ले रहे हैं उनके सामने यह बात आनी चाहिए कि जो जमीन हमारे पास आयेगी उसके बंटवारे का क्या तरीक होगा ताकि जिन लोगों को जरूरत है, जिनके लिए कानून ला रहे हैं उनको लाभ पहुंच सके।

तीसरी बात मैं सीलिंग के साथ लघु सिचाई योजना के संबंध में कहना चाहती हूं। लघु सिचाई की योजनाएं जब तक गांवों में उपलब्ध नहीं होंगी तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अभी तक सरकार ने जो कुछ भी किया है, बड़ी नदी घाटी योजनाएं ले रही हैं, मध्यम सिचाई योजनाएं ले रही है, लेकिन लघु सिचाई की जितनी योजनाओं को सरकार को लेना चाहिये, जो कुछ कार्य करना चाहिये था, वह नहीं हो सका है।

यह सही है के हमारे हिसाब किताब में तो नलकूपों की संख्या बहुत आती है जो हमने गांवों में दिये हैं। अगर असलियत यह है कि इतने अधिक नलकूप नहीं लगे हैं जिसके द्वारा सरकार गाव में किसानों की जमीन की पैदावार बढ़ाने में मदद पहुंचा सके। जो भी गांवो में नलकूप लगे हुए हैं उनकी मरम्मत का कोई प्रबन्ध नहीं है, तो ये सब छोटी मोटी बातें है और जब हम किसान का खेत की जोत सीमा निर्धारित करने की बात करते हैं, तो इन सब चीजो की ओर ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि जब तक जमीन के अन्दर के पानी का प्रयोग द्वारा नहीं होगा तब तक हम अन्न का उत्पादन लक्ष्य के अनुसार नहीं बढ़ा पावेंगे। फर्टीलाइजर का पूरा प्रयोग तभी है जब पानी प्राप्त है।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो नलकूपों का प्रबंधक संगठन है उसके लिए किसान को गांव के सब डिवीजन से लेकर जिला तक में दौड़ते दौड़ते 6 महीने लग जाते हैं। हमारे नलकूपों को लगाने के लिए जो तरीका है, ऋण मांगने का जो विधान है, इसके लिए औजार मशीनरी उपलब्ध करने की जब किसान चेष्टा करता है तो उसको सब-डिवीजन से लेकर जिले तक दौड़ते दौड़ते वर्ष और महीने लग जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक जगह यह बात कही है कि हमारी तीन चार योजनाएं हुई हैं और जितनी वह सफल होनी चाहिए थीं उतनी सफल नही हुई हैं क्योंकि हमारे प्लानिंग कमीशन में जो लोग हैं वे दिल्ली में बैठकर उसका प्लानिंग करते है। वे लोग खूबसूरत और मनपसन्द योजनाएं कागजों में करते हैं। शहर में बैठकर योजना बनाते समय हम ध्यान उनके कार्यान्वयन की सम्भावनाओं पर नही देते हैं। शहर के जो लोग हैं वे गांव के किसानों की मजबूरियों को नहीं समझ पाते हैं। और इसीलिए उपसभापति जी, मेरा कहना है कि सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। सारी चीजें जो हम शहर में बैठकर केन्द्रीभूत करते हैं, उसको बदलें और हमारे प्लानिंग का नक्शा ऐसा बनना चाहिए जिसको ठोस जमीन पर उतार सकें और उसका गांव की तरह झुकाव होना चाहिए। बजाए कि यहां से नीचे जाए, हमें नीचे से ऊपर लाने की जरूरत है। गांव में जो लोग हैं, उनकी जो जरूरतें है वह किस तरह से पूरी हों ठोस जमीन पर क्या दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर सोचना होगा। यह गांवों के अनुभव पर ही सोचा जा सकता है और अभी तक हमारा जो दृष्टिकोण है उसको बदलना होगा और नये दृष्टिकोण से इन सब चीजों को

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

देखना होगा, उनमें सुधार करना होगा और तभी हम जो कुछ करना चाहते है वह कर सकेंगे ।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम गावों तक बिजली पहुंचायेंगे । बात तो अच्छी है और दिखलाई देता है कि लाखों गांवों में बिजली पहुंच गई है लेकिन अभी तक जिन गांवों में बिजली पहुंचाई गई है वहां पर असलियत में क्या हो रहा है ? कागजों में तो लिखा गया है कि हम नलकूपों के लिए बिजली देंगे लेकिन जहां-जहां हमने गांवो में बिजली पहुंचाई है उनके संबंध में हमने कह दिया है कि वहां पर बिजली दे दी गई है लेकिन वहां पर अभी तक बिजली के खम्बे तक नहीं लगे हैं । जहां बिजली पहुंच गई वहां दिन में 6 घण्टे भी बिजली नहीं मिलती है जिससे नलकूप चलायें जा सकें । जिस समय बिजली की जरूरत होती है उस समय बिजली नदारद रहती है और इस तरह से बिना बिजली के नलकूप नहीं चल सकते हैं बिजली लगाने पर इस तरह की दिक्कतें होती हैं और बिना बिजली के किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । हम जिस समय बड़े-बड़े पावर हाउस का निर्माण करने की योजना बनाते हैं उसी समय सम्पूर्ण योजना उन गांवों और शहरों की भी बनानी चाहिए जहां बिजली जायेगी । और उसके साथ ही कार्य आरम्भ होना चाहिए ताकि पावर हाउस जब भी तैयार हों तो उसके साथ ही गांवों और शहरों में सभी प्रबन्ध पूर्ण हों बिजली चालू करने के । इसी तरह से राष्ट्रपति ने अपने 5 P.M. अभिभाषण में शिक्षा के विषय में कोई विशेष बात यहां पर नही कही है । जो शिक्षा का कार्यक्रम है भी उसमें भी गांवों में शिक्षा के कार्यक्रम को किस तरह फैलाएंगे इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है । इस सिलसिले में मेरा कुछ अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जो शिक्षा की अच्छी संस्थाएं हैं, अच्छी योजनाएं हैं, सेन्ट्रल स्कूल की योजना है वह सारी केन्द्रीभूत हो जाती है शहरों में । जब उसे गांवो में ले जाने की बात हम लोग उठाते हैं तो जो अफसर लोग हैं, दूसरे लोग हैं उनका यह कहना होता है कि गावों में हमें इन्टेलेक्चुअल पौटेंशियलिटी उतनी प्राप्त नहीं है जैसी शहरो में है । उनकी यह भूल है; बल्कि सही बात यह है कि अगर गांवों में हम सही रूप में शिक्षा संस्थाए खोलें, शिक्षा के अच्छे इस्टीट्यूशन्स बनाएं तो हमें सफलता ज्यादा मिलेगी इसलिए कि शहर में जो शिक्षा की संस्थाएं हैं, जो शिक्षक हैं और विद्यार्थी है दोनों के लिए बहुत सी दूसरी चीजें ऐसी हैं जो उनका ध्यान आकर्षित करती हैं । इसलिए जितना शिक्षा पर ध्यान जाना चाहिए उतना शिक्षा पर ध्यान नही हो पाता है । इसीलिए हम देखते है कि पिछले समय में क्या था । शिक्षा की जितनी संस्थाएं थीं वे आश्रमों से सम्बन्धित थीं । आश्रमों से क्यों सम्बन्धित थीं । उसके पीछे अवश्य कुछ कारण रहा होगा । इसलिए आश्रमों से सम्बन्धित थीं कि वहां एकान्त स्थान था, वहां विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच आपस में अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती थीं और लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते थे, शिक्षक को अधिक समय मिलता था कि वह अपनी पुस्तकों का अध्ययन करे, अपने विद्यार्थियों का अध्ययन करे कि किस विद्यार्थी में क्या कमजोरी है और इस तरह एक दूसरे के के समीप आने की वजह से जो शिक्षा की क्वालिटी थी वह आज से पहले बहुत

अच्छी थी। आज शिक्षा की क्वालिटी खराब हो गई है। हम कहते हैं कि विद्यार्थियों में असंतोष है। क्यों नहीं नौजवानों में असंतोष होगा ? हम जो उनको शिक्षा दे रहे हैं उसको प्राप्त करने के बाद उनके पास नौकरी प्राप्त करने का आधार नहीं होता है, उनके पास वह शिक्षा नहीं होती है जिससे वे अर्थोपार्जन कर सकें, उनके पास वह शिक्षा नहीं होती है जिससे वे कोई भी राष्ट्रीय निर्माण के काम में हकीकत में हिस्सा ले सकें। हम सिर्फ यह देखते है कि क्वांटिटी कितनी है, नम्बर कितना हुआ, प्लानिंग कमीशन को भी इस बात की ज्यादा जरूरत महसूस होती है कि हम यह दिखाएं कि इतने लाख स्टूडेंट एक स्टेट में पढ़ कर शिक्षित हो गए लेकिन उस शिक्षा से फायदा उतने लाख को हुआ या नही यह नहीं देखते कि अगर सरकारी क्लैरिकल नौकरी हम उनको नही दे सकते तो भी वे अपने पांवों पर खड़े हो सकें, ऐसी शिक्षा दे है कि नही ? हम अभी भी वही शिक्षा का आधार रखे हुए हैं जो अंग्रेजों के जमाने में था। अंग्रेजों ने शिक्षा की यह पद्धति इसलिए रखी थी क्योंकि उन्हें क्लर्क्स की जरूरत थी, उन्हें टैक्नीशियन्स की जरूरत नही थी, डाक्टर्स की जरूरत नहीं थी क्योंकि वे ये अपने देश से ले आते थे, इंजीनियर्स की जरूरत नहीं थी क्योंकि इंजीनियर्स वे अपने देश से ले आते थे किन्तु आज हमें अधिक टेक्नीशियन्स की जरूरत है अपनी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए, अधिक इंजीनियर्स की जरूरत है अपनी सडकों को, अपने डैमों को, हर चीज को बनाने के लिए। आज हमें अधिक डाक्टर्स की जरूरत है (*Time bell rings*) आज मैं पहले पहल बोल रही हूं, आपकी बड़ी कृपा होगी, मुझे दस मिनट समय और दिया जाये। उपसभापति महोदय, इसलिए मैं आपके द्वारा यह कहना चाहती थी कि हमारी शिक्षा की पद्धति में नया सुधार, नया दृष्टिकोण और नई व्यवस्था लाने की जरूरत है ताकि हम अपने नौजवानों में एक नया जोश देख सकें और नई धारा में उन्हें प्रविष्ट कर सके। जो अभी हो रहा है, जो सिस्टम है, उससे जो चाहते हैं वह नहीं हो पाता है। उपसभापति महोदय, हमारे सूबे में—बिहार की बात मैं कहती हूं—एक तरफ हमारे पास सड़कें नहीं हैं, एक तरफ हमारे पास फैक्ट्रीज नही हैं, हमारी खानों में सब कुछ मौजूद है लेकिन हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है। रिजर्व बैंक में देखा जाये, इंडस्ट्रियल बैंक में देखा जाये, हमारे सूबे की किसी इंडस्ट्री के लिए कोई ऋण नहीं मिला है। कितना पैसा गुजरात को मिला है, कितना महाराष्ट्र को मिला है और कितना बिहार को मिला है। दूसरी तरफ ढाई हजार, तीन हजार, चार हजार इंजीनियर बेकार पड़े हैं। इन दोनों बातों में समता क्यों नहीं आती है ? क्यों प्लानिंग कमीशन, नया ओरिएंटेशन, नया आउटलुक नहीं ला पाता है ?

यह ठीक बात है कि इंदिरा गांधी की सरकार को मैंसिव मैन्डेट मिला है। मैं वैसा नहीं मानती हूं जैसा कि विरोधी दल के लोग कहते है कि इस महान विजय के पीछे कोई गूढ रहस्य है। क्योंकि पिछले चुनाव मे मै स्वयं बहुत सी जगहों पर गयी और मैंने बहुत से बूथ्स को देखा। सही बात यह है कि इंदिरा गांधी की सरकार को वोट इसलिए मिला है क्योंकि लोगों में एक नयी आशा जागृत हुई कि ये गरीबों के लिए कुछ कर सकेंगी, हमारे नौजवानों में यह आशा जागृत हुई कि ये हमारे इंजीनियर्स के लिए कुछ कर सकेंगी, हमारे डाक्टर्स के लिए कुछ कर सकेंगी और गरीबों के लिए एक नयी धारा इस देश में बहा सकेंगी

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

लोग जाग उठे हैं। तो उपसभापति महोदय, इन सब बातों को देखते हुए जब तक कि हम एक नया ओरिएन्टेशन अपनी सारी योजनाओं में न करें तब तक जो कुछ भी आशा लोगों में बंधी है वह पूरी नही हो सकेगी। इसलिए आपके द्वारा मै सरकार से यह विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहती हूं कि जब हम योजना बनावें तो योजना किस प्रकार कार्यान्वित हो सकती है, इसके पूर्ण विवरण में अवश्य जावें। उदाहरण के लिए अगर हमको भूमि सुधार करना है तो उसके लिए हम सारे डिटेल्स में जायें, उनको वर्क आउट करें कि किस सूबे में किस तरह का काम करने से हमारे उत्पादन की स्थिति सुधर सकेगी। हम अपनी शिक्षा की पद्धति में सुधार लाये और ऐसे सुधार लायें कि जिससे जो हमारे नौजवान हैं, जिनके दिलों में नयी आशायें बंधी है, उनको काम मिलने में सुविधा हो और उनकी शिक्षा केवल क्लर्क बनने की ही न हो; बल्कि अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे डाक्टर्स और अच्छे इंजीनियर्स बनने की हो और साथ इन इंजीनियर्स को लेकर हम सड़कों और पुलों का निर्माण कर सकें, डाक्टरों को हस्पताल अधिक बना कर उपयोग मे ला सकें और वैज्ञानिकों मे नये अनुसंधान करा सकें।

अन्त में यह कहना चाहती हूं कि यह जो प्रीवी पर्सेज का इश्यू है, यह भूतपूर्व राजाओं और रियासतों की मान्यता का सवाल है यह सही बात है उपसभापति महोदय, कि क्या हमारे पास है, हम किस आधार पर यह कह सकते है कि एक तरफ प्रिन्सेज के पास इतना धन है कि उनके जानवरों को भी जो सुख सुविधा प्राप्त है उनके कुत्ते भी जो बिस्कुट खाते हैं, उनके मुकाबले हमारे गांव के साधारण बच्चों को अनाज भी नसीब नहीं होता है, आज भी हमारे बहुत से गांव के लोग कुएं का पानी पीते हैं, उसका गंदगी से रंग हरा रहता है तो किस औचित्य पर आप प्रीवी पर्सेज को रखना चाहते हैं ? किस औचित्य पर आप इन सुविधाओं को उनके लिये बनाए रखना चाहते हैं कि उनको मुफ्त की बिजली और पानी मिलता रहे, उनको जब चाहें विदेश आने जाने की स्वतंत्रता हो। दूसरी तरफ हमारे जो औद्योगिक विकास के काम हैं वह हम न कर सकें, हमारी सड़कें और हमारे स्कूल न बन सकें और हमारे गांवों में अस्पताल न बन सके, वहां बिना दवा के लोग मर जाये और दूसरी तरफ हम प्रिन्सेज़ को मान्यता जारी रखें। हम कहने को कहते हैं कि उन्होंने बहुत त्याग किया था क्योंकि छः सौ रजवाड़े उस समय बगावत भी कर सकते थे किन्तु जनता उस समय इन रजवाड़ों की भी कांग्रेस के साथ थी और यदि प्रिन्सेज़ बगावत करते तो उनकी हालत भी चुनाव के बाद आज जो प्रतिक्रियावादियों की हुई वही होती। सही बात यह है कि उन्होंने हवा के रुख को देखा। उन्होने देखा कि अगर वे हमारे साथ कदम से कदम मिला कर नही चलते है तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर प्रीवी पर्सेज को खत्म करने के लिए, जैसी समय की मांग है, यदि कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन भी करना पड़े तो हमे कांस्टीट्यूशन जरूर अमेंड करना चाहिए, क्योंकि समय की मांग जो होती है, समय की पुकार जो होती है उसको यदि सरकार नहीं समझती है तो आगे बढ़ने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं। इसलिए उपसभापति महोदय, मुझे कुछ और भी बातें कहनी थीं, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए मैं समाप्त करती हूं

और आखिर में एक बात और भी कह देना चाहती हूं कि अगर सचमुच में हम नया हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं, तो हमें एक चीज और सुधारनी होगी। वह है ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी जो हमारे कार्यकर्ताओं का सिलसिला अभी तक है, जिस ढंग के उनके विचार हैं, जिस प्रकार की उनके काम करने की प्रणाली है और जिससे हर काम में रुकावटें होती है, उसको सुधार कर ही हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए भी यदि संविधान में संशोधन की आवश्यकता हो तो करना है। अगर यह कार्यकर्ता समय के अनुसार अपने ढांचे को बदल सकें, तो उनको आगे बढ़ने देना चाहिए, उनका प्रमोशन होना चाहिए और जो लोग प्रोग्रेसिव मेजर्स में बाधा दें उनके ऊपर कुछ कार्यवाही भी होनी चाहिए, नहीं तो उनकी वजह से ही सारे प्रोग्रेसिव मेजर्स असफल रह जाते हैं। हम लोग उसके लिए कदम उठाते हैं। कानून बना देते हैं, लेकिन उसमें हम पूर्ण रूप से सफलीभूत नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान देकर जो मैसिव मैन्डेट हम को मिला उसके अनुसार हमें अपने काम को जल्दी आगे बढ़ाना है; क्योंकि यह सही बात है कि जिस तरह से हवा का रुख इन्दिरा जी के साथ है, अगर हम उस हवा के रुख को पकड़ कर तेजी से आगे न बढ़ सके तो इसमें कोई शक नहीं कि वह हवा का रुख बदल भी सकता है और यह हमें नहीं होने देना है।

SHRI A. K. MANI : Mr. Deputy Chairman, Sir, the President's Address to the joint session of Parliament is a disappointing document. I hope in future the Address will be written by politicians, and not by civil servants. I can show you a lot of errors. They say here, "As part of this exercise .... ." This is the Phrase used by the bureaucrats. They say: "As part of this exercise, Government will also identify the specific directions in which developmental programmes could be further reinforced in a determined effort to deal with the problem of unemployment .....". Is this the way the leaders of the people will write? This is the way in which civil servants will ....

(*Interruption*)

We all expect that some light would be thrown on the steps Government are taking to solve the problem of un-employment in this country. According to statistics available, 39 million persons are registered in the unemployment registers of employment exchanges all over the country. And as many as 5 million come from Bengal, 4 million from U.P. and 4 million from Tamil Nadu. In these centres there is a good deal of discontent about the state of unemployment.

Sir, according to the amendment that I submitted, an unemployment allowance should be given to those who are unemployed. There are persons who remain unemployed after taking degrees from colleges for three or four years and such persons are the focus of this suggestion. For this reason I suggested that an unemployment allowance should be given. It need not be always on a permanent basis. But some efforts should be made to get them employed. Sir, one of the ways in which the problem of unemployment can be tackled, is to intensify our agricultural and industrial development. We do not have statistics of the rural unemployed. According to statistics available, there are persons who are employed only for 160 days in a year. It requires effort to see that such persons are employed for at least 240 days in a year. And it can be done only by intensive agricultural development.

Sir, in Kerala an experiment has been made by qualified technicians to start cooperatives of their own for production of scooters. My friend here is connected with one such enterprise.....

(*Interruption*).

The Government should try to help such cooperatives, and even in private companies of technicians which have been formed it

[Shri A.D. Mani.]

can take shares to see that these persons are employed.

Sir, I would like to say here that there has been a reference to the land reforms. There are millions of small landholders. If they are deprived of their land—we are not talking of big estate-holders, about the princes, zamindars, etc., but about the small land holders, they will greatly suffer. They must get adequate compensation for it, and the ceiling may be practical. My friend, Shri Sheel Bhadra Yajee was a member of the Land Acquisition Committee along with me, and we came across this problem of compensation to small land-holders for the sake of big projects.

I would also like to suggest that we should take energetic steps to relieve the housing shortage in this country.

Now, we always think in terms of brick and mortar and cement and concrete in regard to housing shortage. We have got to consider the state of the houses in the various villages of this country. A new type of house will have to be constructed which will enable the peasants to carry on agricultural operations. It is impossible for a farmer to carry on agricultural operations in a hutment made of cement concrete and we should mobilise the help of the State Governments to have a crash programme for the construction of houses.

Sir, the second point I would like to make is that there is a reference to the massive mandate of the people that the Government has secured in the elections. There is no doubt whatever that the people have shown that they want stability in the Central Government and they have given their overwhelming confidence for the Government led by Mrs. Gandhi. Now, this massive mandate has also been a vindication of our democratic procedures and processes but the election has shown certain defects. The Election Commission should not become a super lord in the democratic set-up. According to the Constitution there is a provision for the Election Commission being expanded. We should also have Regional Commissions who will have intimate knowledge of the voting and polling conditions in the various States. The other day a question was asked about the ballot papers in Chandigarh. I believe that the elections have been free and fair all over the country though there might have been irregularities in some polling stations. But in the case of Punjab, in Chandigarh a large number of voting papers were left with the printing press. That should never be done. The procedure which is adopted by university authorities when they print question papers is that all the copies of the question papers including the wastage are taken away by the university. Nothing is left behind. Why should the Election Commission allow a wastage of 5 per cent in the printing of ballot papers and leave it with the Stationery and Printing Department in Chandigarh?

The other point is this. These elections have shown that it is very difficult for us to conduct elections in this country because the limit on expenditure has been fixed as Rs. 35,000 for a Lok Sabha constituency. Sir, you yourself, as one who has campaigned in the Vidarbha area, know how costly it has become to conduct an election in this country. According to estimates these elections have cost us anywhere between 15 and 20 crores of rupees. That does not matter in terms of money if so much money is spent for an experiment in democracy.

Sir, we should also take into consideration the fact that the parties in opposition are in a disadvantage compared to the party in power; I mean, the party in power always enjoys certain advantages. I would like to suggest for the earnest consideration of the Government that we might consider adopting the West German parallel where parties which get a certain percentage of the national vote are given free assistance by the State itself to conduct election campaigns. This has been done even in Pakistan. There are smalll parties, there are parties which have registered a certain percentage of votes in the Lok Sabha mid-term poll and, if they qualify within a certain percentage they should be given free assistance.

Another point is, in this election the newspapers of India—I am very sorry to say—were against the party in power and the party in power has shown that newspaper propaganda does not count. And it did not count even in a country like Great Britain when the Labour Party won the election in spite of Fleet Street and the big business barons who own the newspapers in England. But, Sir, one criticism I have heard, and I say this as one who has been an independent journalist in this country, that the Government had the advantage of the All India Radio in their hands. The All India Radio's broadcasts and news bulletins have been generally fair. But sometimes one could pick upon one bulletin and say something like this. It is for this reason that the time has come now that the elections have become a part of our national life we have to go through many other elections in the future and the democratic set-up has come to stay. in India—that we must give the opposition parties adequate time both on the TV and the All India Radio to reach the villages.

This was not done in a marked manner in the last elections. To that extent the scales were slightly tilted in favour of the ruling party. Very few read the papers but millions listen to the radio and it is for this reason that the Cheif Election Commissioner, who is a very valuable and loquations person, who goes on issuing statements about proportional representation being not suited to India, should call a conference of the concerned parties who have secured a certain percentage of votes and evolve a procedure by which in the future election the AIR and the TV madia wherever it is set up will be available for propaganda of putting forward the point of veiw of the various parties.

I have table I an amendment that there should be a ceiling on urban property but before the ceiling is fixed, we should try to ascertain what hould be the ceiling State-wise. A man owning a house in Delhi with three bedrooms may have a property worth Rs. 4 lakhs but a man having a house with three rooms in a place like Chindwara will have property worth Rs. 50,000 only. You go to Jor Bagh and you will find houses worth Rs. .5 lakhs. I would like to say that we should have a State-wise survey of what should be an adequate ceiling on urban property.

Lastly, Mr. Banka Behary Das wanted a constitutional Reforms Commission to be appointed. I am in favour of it. I do not think the question of the Constitution should be open because we have not come to that stage of a consensus being arrived at on the basis of the Constitution but certanly a Reforms Commission should be appointed to consider the question of the amendment of the Constitution regarding one Fundamental Right, namely, the right to property. There should be the right to personal property. What should be the limitation to be put on the right to property we shell consider but I do not want other Fundamental Rights to be reopened because they would be sacrosanct. Mr. Hidayatullah said it is the weakest of the Fundamental Rights, it is for that reason that we should have a rethinking on this question of the right to property.

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : मिस्टर डिपुटी चेयरमैन, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर श्रीमती पूरवी मुखर्जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं । अनुमोदन करते हुए मुझे राष्ट्रपति जी से भी शिकायत है, और अपनी सरकार से भी शिकायत है, कि जब इस चुनाव में इतना भारी जनता का समर्थन मिला और वह समर्थन इसलिए मिला कि उन्होंने कहा कि समाजवाद की स्थापना होगी, गरीबी मिटाई जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उसका जिक्र तक नहीं किया । अनइम्प्लाएमेन्ट दूर होगा, देहातों में बिजली जाएगी, गरीबी दूर होगी गोल-गोल शब्दों में जो हमारी सरकार बोलती आई थी, फिर गोल-गोल शब्दों में बोलना शुरु कर दिया, जीतने के बाद । जब हम कहते आए हैं, और हमारा यह मैंडेन्ट

[श्री शीलभद्र याजी]

रहा है कि हम समाजवाद की स्थापना करेंगे, तो राष्ट्रपति जी जिन्होंने बहुत दिनों तक मजदूरों में काम किया है, कम से कम उनको उसका निजी तजुर्बा है और श्रीमती इन्दिरा गांधी समाजवाद के बारे में इतने भाषण देती थीं, उनके लिए यह उचित ही था कि अपने अभिभाषण में इसका जिक्र करते, इस साल नहीं तो अगले वर्ष में हम अपना कांस्टीट्यूशन अमेन्ड करके, उसमें परिवर्तन करके, भारतवर्ष को एक सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाएंगे, यह घोषणा होनी चाहिए। गरीबी दूर होगी बेकारी को दूर करके, बेकारी के भत्ते से नहीं। आखिर बेकारी का भत्ता कहां से मिलेगा ? 50 करोड़ की हमारी आबादी इस मर्दमशुमारी में 56 करोड़ होने वाली है, जहां कि बारह, तेरह करोड़ लोग अभी बेकार है, इन्जीनियर लोग बेकार घूमते हैं। 50 करोड़ रुपया बेकारी दूर करने के लिए रखा गया है। सरकार के पास पैसा नहीं है, न योजनाओं को चलाने के लिए पैसा है, न बेकारी दूर करने के लिए पैसा है और न ही कल कारखानों को चलाने के लिए पैसा है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि वह इस देश में समाजवाद की स्थापना करना चाहती है। तो सब से पहले उसको जितनी भी देश में कल कारखाने है, बागान है, जो बैंक छूट गये हैं, विदेशी बैंक है, विदेशी कंसर्न है, उन सब का समाजीकरण कर दिया जाना चाहिये और उनको एक पैसा भी मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिये।

कम्पनसेशन देने की जो बात कांस्टीट्यूशन में आई है, वह एक गलत चीज है। हमारे श्री मणि साहब इस चीज की दुहाई दे रहे थे, जो अपने को जर्नलिस्ट कहते हैं। वे कहते हैं कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं होना चाहिये। वे अपने को समाजवादी भी कहते हैं और कभी अपने को उग्रवादी भी कहते हैं। उनका इस तरह का जो दृष्टिकोण है, वह एक रिएक्शनरी की तरह है। (*Interruptions*) हमने मणि से एक सवाल पूछा था कि मौलिक राइट, फन्डामेंन्टल राइट, जिसके मातहत पहले राजा महाराजाओं को लूटने की इजाजत थी, क्या उसको रखा जाय। इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। (*Interruptions*) यह जो हमारा कांस्टीट्यूशन है, वह चू चू का मुरब्बा है, वह न कुरान शरीफ है और न ही मनुस्मृति ही है। यह जो अपने को पत्रकार कहते है, अपने को बुद्धिमान समझते है, वे राजा महाराजाओं तथा कैपिटलिस्ट लोगों की छिपे रूप में समर्थन करते हैं और कहते है कि फन्डामेन्टल राइट्स में कोई चेन्ज नहीं होना चाहिये।

श्री ए० डी० मणि : मैंने कहा था कि फन्डामेन्टल राइट टु प्रापर्टी को चेन्ज नहीं करना चाहिये। दूसरे फन्डामेन्टल राइट्स को मै पाक मानता हूं। I do not want Fundamental Rights to be changed.

श्री शीलभद्र याजी : उपसभापति महोदय, मैंने कई बार और प्रधान मंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि फन्डामेन्टल राइट्स में जो संशोधन होगा, जो तरमीम होगी वह केवल फन्डामेन्टल राइट्स टु प्रापर्टी जो है उसको हम लिमिटेड प्रापर्टी करने जा रहे हैं; क्योंकि राजा महाराजाओं के पास जो 50 हजार एकड़ जमीन है, कुत्तों के नाम से 400 एकड़ जमीन है उसको हम लिमिटेड कर देना चाहते है।

श्री ए० डी० मणि : मै मानता हूं।

श्री शीलभद्र याजी : इसलिए मैं अपनी सरकार से बार-बार शिकायत करता हूं इस सदन में और बाहर भी क्योंकि हमारी सरकार की यह आदत पड़ गई है, एक पुरानी आदत जिसमें सब गन्दे लोग मिल गये थे।

एक माननीय सदस्य : अब तो वही पुराने लोग फिर से आ रहे है।

श्री शीलभद्र याजी : हमारे साथ जो पुराने लोग थे, गन्दे लोग थे, उन्हें निकाल दिया गया है और उन्ही की वजह से इस काम में रुकावट पड़ रही थी। हमारी सरकार तो कछुए की गति से चलती है, टोरटाइज की गति से चलती है। हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई मौलिक परिवर्तन की बात नही पाते हैं। सरकार को इस बात को समझना चाहिये कि उसे किस तरह की मार्शल विक्ट्री हुई है, समाजवाद की जीत हुई है, इसलिए मै सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वह सचमुच में इस देश में समाजवाद की स्थापना करना चाहती है, गरीबी को दूर करना चाहती है तो उसको जल्दी निश्चय करना चाहिए और भारत को सावरेन सोशलिष्ट पब्लिक डिक्लेयर कर देना चाहिये तथा नेशनलाइजेशन में जल्द से जल्द तरमीम होना चाहिये। जितने भी प्राइवेट सेक्टर में चीजें है, चाहे कल कारखाने हों। बागान हों, जितनी भी इन्डस्ट्रीज हों, बैंक्स हों, जो छूट गये है, इन सबका जल्द से जल्द राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। इस तरह से हमारे पास इतना पैसा हो जायेगा, जिसमे हमें न अमेरिका से, न कैनेडा से और न रूस से ही पैसे मांगने की जरूरत पड़ेगी। 75 परिवारों के पास जितना हिन्दुस्तान का ज्यादा पैसा है वह ले लेना चाहिये। लेकिन मैं इस बात को बार-बार कहता हूं, मगर यह सरकार सुनती नहीं है।

मैं फिर दोहराता हूं कि एक पैसा उनको मुआवजा न दे। वैसा करें जैसा लेनिन ने किया कि सारे के सारे जितने पूजीपति हैं, उन्हें कल-कारखानों में लगा कर दस हजार रुपया, जो गवर्नर्स को मिलता है, महीने दिया, टाटा, बिड़ला को दस-दस हजार दिया जाय, उनको तजुर्बा है, आई० सी० एस०, आई० ए० एस० जिन्हें इंडस्ट्री चलाने का ज्ञान नहीं उनको इंडस्ट्री में लगाते हैं, तभी घाटे पर घाटा आता है और जन-संघियो और स्वतंत्र पार्टी के लोगों को मौका मिलता है यह कहने का कि घाटे पर घाटा आ रहा है। इसलिए मुआवजा एक पैसा नहीं देना चाहिए। अगर हम राष्ट्रीय-करण करते हैं तो हमारे पास इतनी पूजी हो जायगी कि नए करखाने खोले जा सकेंगे, बेकारी कम की जा सकेगी। 50 करोड़ रुपए क्या हैं, हम हजारों करोड़ रुपए जो अनएम्प्लायड लोग हैं उनको मासिक दें जब तक नौकरी उनको नहीं देते।

अभी राष्ट्रपति जी ने कई बातें कहीं, परन्तु मनीपुर, मेघालय, त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया जायेगा, बिल आएगा नही कहा। यह क्यों ? 1972 में इलेक्शन है, सरकार से हमारी गुजारिश है कि सिर्फ मनीपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लिए ही नहीं बल्कि सरकार को कुछ और ठोस कदम इस सम्बन्ध मे उठाना चाहिए। मिजो में सशस्त्र आन्दोलन चल रहा है। पाकिस्तानी लोग उन्हें ट्रेन्ड करते हैं, वे भी स्टेट मांगते हैं। छोटी-छोटी स्टेट नहीं बन सकती है, चाहे इसे मनीपुर में मिलाइए या कछार को त्रिपुरा में या त्रिपुरा को आसाम में मिलाइए, बाउंडिगुअल स्टेट कीजिए, लेकिन यह छोटी-छोटी स्टेट दो लाख, तीन लाख की आबादी

[श्री शीलभद्र याजी]

की सम्भव नही है । डिपुटी चेयरमैन साहब ने एक बार फरमाया था और सही फरमाया था कि इतने लाख की आबादी पर स्टेट नहीं बन सकती है । लेकिन जब भाषा के आधार पर हमने प्रान्तों का निर्माण किया है और मनीपुर, त्रिपुरा को भाषा के आधार पर जब स्टेट घोषित कर दिया तो जल्द से जल्द विधेयक अगले बजट सेशन में अवश्य आना चाहिए ताकि लोगों को जो वे चाहते हैं मिले । उसके साथ-साथ जनता की आवाज को मानना चाहिए, हम चार बार बोल चुके है, गोआ, दमन और दीव के लोगों ने अपनी असेम्बली में प्रस्ताव पास किया है कि उनको स्टेटहुड दिया जाये, उनको भी देना चाहिए ।

इसी के साथ-साथ जो कदम हम उठाएं वह तेजी से उठे, जो रफ्तार अभी है, उससे समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती । इसलिए हम सरकार से शिकायत करते है और राष्ट्रपति जी को भी कहते हैं, राष्ट्रपति हैड आफ दि स्टेट हैं, उनको बहुत अधिकार हैं, वे अपने प्रधान मंत्री को कहें कि अगर उनकी सरकार तेज नही चलती है तो उसे अपनी रफ्तार को तीव्र करना चाहिए । अगर रफ्तार मे तीव्रता नही आती तो हमारे लिए खतरा है । जो निर्देश आपको जनता से मिला है, इतना भारी निर्देश मिला है---जितने लीडर लोग ग्रान्ड एलाएन्स, विशाल गठबन्धन में थे, चरण सिंह कैबिनेट बनाते थे, सब धराशायी हो गए---उसके बाद भी हमारी बुद्धि नहीं सीधी हो रही है, यह बड़े आश्चर्य की बात है ।

हमारी सरकार ने यह एक शाबाशी का काम किया, सब पार्टियों ने मिल-कर एक प्रस्ताव पास किया । बंगला देश में आन्दोलन है । पाकिस्तान की शिकायत है कि इन्टरफियर करते हैं, इन्टर्नल एफेयर्स में । मैं कहना चाहता हूँ पाकि-स्तान को भी और सारी दुनिया के लोगों को भी कि यह इन्टरफियरेंस नही है । जब जनता के नुमाइन्दे चुन कर आते हैं अक्सरियत उनकी होती है, उनको गद्दी पर नहीं बिठा कर हिटलर मुसोलिनी वाला डंडा चलता है तो पार्लियामेंट में हम जरूर आवाज उठाएंगे चाहे वह कहीं भी हो । यह तो हमारे बगल की बात है, थोड़े दिन हुए हमें अलग हुए । इलेक्शन हुआ, उसके बाद मुजीबुर रहमान को प्रधान मंत्री बनना था, भुट्टो कहता है हम प्रधान मंत्री बनेंगे । एक देश में दो प्रधान मंत्री कैसे हो सकते हैं । वहां डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है । सरकार ने जो कदम उठाया गोल गोल उससे बात गोल ही रह जायेगी, साढ़े 7 करोड़ में से 7 लाख लोग मारे जा चुके हैं । फिर भी पाकिस्तान रेडियो रोज बोलता है, भारत सरकार खूब मदद करती है और हम केवल मौखिक दान दे रहे है । मौखिक दान से काम नहीं चलेगा । यू० एन० में इस सवाल को उठाना चाहिए और हमें उसको फौरन रिकगनिशन देनी चाहिए । चूंकि जनता ने उसको चुना है, पाकिस्तान की जनता ने उसको चुना है, वह सही सरकार है और इसलिये उस सरकार को मान्यता प्रदान कर जो भी उनको इमदाद, आल आउट सपोर्ट जिसको हम कहते हैं, वह मिलनी चाहिये । इसी में हमारा भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है और दुनिया में शांति भी रह सकती है । जब हम आजादी की लड़ाई लड़ते थे तो हम अपने आप तो लड़ते ही थे, लेकिन दुनिया की आज़ादी के लिये, जम्हूरियत के लिये हम बराबर अपनी आवाज बुलन्द करते थे । अब जब मौका आ गया है, हम पावर में भी हैं, शक्ति में भी हैं

तो हमें अब भी अपनी आवाज बुलन्द करने में पीछे नही रहना चाहिये। आज वहां हमारे भाई कत्ल हो रहे है, हमारी बहनें मारी जा रही हैं और हिटलर और मसोलिनी ने जो जुलम नही किया वह आज जनरल याहया खान कर रहा है। तो इसमें सिर्फ मौखिक सहानुभूति जाहिर करने से काम होने वाला नहीं है। उसको रिकगनाइज करके हर तरफ की आल आउट सपोर्ट उसको देनी चाहिये। यही हमारी सरकार से गुजारिश है। जय हिन्द।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) in the Chair]

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उप-सभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में आम चुनावों के सम्बन्ध में बड़ी चर्चा की गई है। राष्ट्रपति महोदय ने यहां तक कहा है कि मेरी सरकार को बहुसत मिला है। मुझे इस शब्द पर आपत्ति है कि राष्ट्रपति जी की सरकार को बहुमत मिला है। यानी राष्ट्रपति जी की सरकार ने चुनाव लड़ा है। चुनाव विभिन्न विभिन्न पार्टियों ने लड़ा है लेकिन मुझे इस शब्द से ऐसा लगता है कि जो बात वास्तव में थी वह राष्ट्रपति जी के मुह से प्रकट हो गई।

श्री शीलभद्र याजी : संविधान के अनुसार ऐसा ही होता है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप बैठिये।

श्री शीलभद्र याजी : यही कायदा है। आप सीखने की कोशिश कीजिये। आप नये आदमी है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चुनाव हुए हैं और उन चुनावों में जिस प्रकार से सत्ता का और साधनों का दुरुपयोग हुआ है वह आज एक चर्चा का विषय है, जांच का विषय है। मतपत्रों के सम्बन्ध में सरकार ने भी कहा है कि हम जांच करवा रहे हैं। यह एक अलग विषय है। लेकिन जो मुख्य तथ्य है वह मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। आज आप यह कहें कि दो तिहाई बहुमत हमें मिला है, लेकिन जहां तक मतों का सवाल है कितने पर सेंट आपको वोट मिले और कितनी सीटें आप को मिलीं। जन संघ को एक करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं और कांग्रेस को लगभग 6 करोड़ वोट मिले हैं। अगर इसकी तुलना की जाये तो आपको हम से छह गुनी ही सीटें मिलनी चाहियें। लेकिन सीटें आप को बहुत ज्यादा मिली हैं। इसका कारण यह है कि जो हमारे चुनाव की व्यवस्था है, जो हमारे चुनाव की पद्धति है वह दोषपूर्ण है। इस लिये हम को उसे बदलना चाहिये। आज जनता का क्या मत है, जनता किस प्रकार की सरकार चाहती है, केवल एक सीट के आधार पर जो चुनाव की पद्धति है उसके सम्बन्ध में केवल यही कहूंगा कि यह चुनाव सही माने में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इस लिये हम को चुनाव की पद्धति में परिवर्तन करना पडेगा। आज हुआ यह है कि कांग्रेस को 40 पर सेंट या 45 पर सेंट वोट मिले हैं और सीटें उसको दो तिहाई मिल गई हैं। यह कहना कि हम को बडा समर्थन मिला है, सारी जनता हमारे साथ है, ये चुनाव के जो आंकड़े है, चुनाव में जो वोट पड़े हैं, उनके विश्लेषण से स्पष्ट लगता है कि वोट के आधार पर पार्टियों को सीटें नहीं मिलती हैं अपने देश के अन्दर। इस लिए इसके अन्दर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिये कि किस प्रकार की पद्धति अपनाई जाये जिस से जिस प्रकार के जनता के मत हों उसके आधार पर सरकार अपने देश के अन्दर बने।

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया जा रहा है, वह सही बात है और उस नारे पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन गरीबी हटाओ के सम्बन्ध में वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया है क्या वह बजट इस आकांक्षा की पूर्ति करता है। 50 करोड़ रु० का कैश प्रोग्राम आपने बनाया है। पिछली बार भी इसी मद के अन्दर 25 करोड़ रु० आपने रखे थे। लेकिन पिछली बार 25 करोड़ रु० रखने के बाद केवल 6 करोड़ रु० आप खर्च कर पाये। बाकी रुपये लेप्स हो गये थे। यानी गरीबी हटाओ, लोगों को रोजगार दो, इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषय में भी किया गया प्रावधान अगर लैप्स हो जाता है, तो इस बारे में हम इस सरकार से क्या अपेक्षा करें। 50 करोड़ की राशि के बारे में बड़ी चर्चा की गई है। हिन्दुस्तान की आबादी जैसा कि हमारे पूर्व वक्त कह रहे थे कि इस जनगणना के बाद 56 करोड़ हो जायगी और 56 करोड़ लोगों में इन्कम टैक्स देने वाले कितने लोग होंगे ! बहुत कम है। बाकी बचे लोगों के अन्दर एक-एक रुपया भी बांटें तो यह 50 करोड़ हिस्से में नहीं आता है। हिन्दुस्तान के जो लोग बेकार हैं, जिन की संख्या 4 या 5 करोड़ के लगभग बताई जाती है, उन पांच करोड़ लोगों के अन्दर अगर इस राशि का वितरण किया जाये तो उनको रोजगार मोहैया नहीं हो सकता।

इस लिए जो योजना हमने बनायी है, जो इस साल का बजट बनाया है, वह वोट आन एकाउन्ट है, लेकिन जो सारी स्थिति है उससे सरकार की योजना तो हमारे सामने आ जाती है और उसके आधार पर अगर हम कहें कि हम लोगों को रोजगार दे सकेंगे, गरीबी मिटा सकेंगे तो वे होने वाले नहीं है और इस लिए सरकार की जो पंचवर्षीय योजनायें हैं उनमें सरकार को बदल करनी चाहिए और सरकार को इस दिशा में विचार करना चाहिए। जो वायदे आपने चुनाब में किये थे चुनाब में जो घोषणायें की थी उनको आप को पूरा करना है। आज देश में जिस प्रकार की परिस्थिति है उसको देखते हुए आपको सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों को हल करना है। देश में जिस प्रकार अराजकता बढ़ रही है, उन अराजकतावादी तत्वों को रोकने के लिए जब प्रश्न उठाया जाता है तो सरकार की तरफ से जवाब आता है कि यह सोशियो इकोनामिक सवाल है, लेकिन आज उसको हल करने की दृष्टि से आप को अवसर मिला है। आप दावा करते हैं कि चुनाबों में आपको बहुमत मिला है, जनता का समर्थन आपको मिला है, उसकी एक हवा है और उस हवा में झूमते हुए आप दिखाई देते हैं, लेकिन उसका क्या इलाज आपने ढूंढा है। आप जो बजट लाये हैं उसके अंदर आपने इस रोग का कोई निदान रखा है ? मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप इस रोग का निदान ढूंढ सके हैं या इसके इलाज के लिए आपने कोई योजना बनायी है कि जिससे देश में बेकारी समाप्त हो सके। विशेष रूप से राजाओं के प्रीवी पर्स के बारे में हमारे कई सदस्य बोले हैं। उनका कहना है कि इन पर्सेज को समाप्त होना चाहिए। एक यह ऐसा विषय है कि जिस पर इस सदन में विचार होगा और उस पर मतदान होगा, लेकिन एक सवाल है यह कि आज देश में आर्थिक असमानता है। गरीब और अमीर के बीच एक बड़ी खाई है और उसको पाटने की दृष्टि से क्या केवल राजाओं के प्रीवी पर्सों को समाप्त करने से, उनका यह चार करोड़ रुपया लेने से जो आज देश में असमानता

दिखायी देती है वह समाप्त हो जायेगी। बेरोजगारी की आज एक समस्या है, उसकी भावना लोगों में है। अपने मंत्री-मंडल के जो सदस्य बैठे हैं सत्तारूढ़ दल के अंदर जो लोग हैं, वह आज अवसर यह इशारा करते हैं कि विरोधी दल में तो राजा लोग बैठे हैं, उन में पूंजीपति लोग बैठे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल के लोग जरा अपने गिरहबान में मुंह डाल कर देखें कि उनके पास किस तरह के लोग हैं। किस तरह के पूंजीवादी, जमींदार, राजा और जागीरदार उनके पास हैं···

श्री शीलभद्र याजी : है, लेकिन उन्होंने समाजवाद को मान लिया है। वह राजाओं के साथ नहीं हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जिस समाजवाद की बात पं० जवाहरलाल नेहरू किया करते थे वह समाजवाद आज लागू नहीं हो सकता। आप की पार्टी में भी आप जैसे लोग घुसे बैठे हैं जो उस के मार्ग में रोड़ा बनेंगे। तो यह एक मूल सवाल है बेकारी का, और आर्थिक असमानता को समाप्त करने का जो प्रश्न है वह केवल राजाओं के प्रीवी पर्सेज को समाप्त करने से हल नहीं होगा। आप को इस प्रकार के कदम उठाने होंगे कि कितनी आय को लेवी हम निर्धारित करें और उन में एक और बीस या एक और तीस या एक और दस से ज्यादा अंतर नहीं रहना चाहिए। इस अंतर को आप तय करिये। आज 23 साल हो गये, केवल गाली देने से काम नहीं चलेगा। आज निर्णय करने का अधिकार आप के पास है। आप संविधान को बदल सकते हैं। आप को 2/3 बहुमत मिल गया है और इसलिए आप को संविधान को बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उसके लिए कानून लाइये। लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानता को मिटाने के लिए कानून लाइये। उस में हम आप का समर्थन करेंगे। केवल नारे के आधार पर, प्रीवी पर्सेज को समाप्त करने के नारे के आधार पर यह मसला हल होने वाला नहीं है। इस के लिए संविधान को बदलने की क्या आवश्यकता थी। आवश्यकता यह थी कि आज लोगों को रोजगार दिया जाये। राइट टु वर्क का सिद्धांत आप संविधान में स्वीकार करिये। हम उस में आप का साथ देंगे। लेकिन आप ऐसा विधेयक सदन में रखिये तो। उपसभापति महोदय, आज इस प्रकार का कोई विधेयक लाने की सामर्थ्य इस सरकार में नहीं है। वह जानते हैं कि अगर इस प्रकार का विधेयक हम तो लायेंगे तो सरकार के ऊपर उस के साथ कुछ जिम्मेदारी भी आयेगी। उस जिम्मेदारी से बचने की दृष्टि से आप ऐसा विधेयक लाना नहीं चाहते। इसलिए मैंने निवेदन किया कि आज जो समस्यायें देश के सामने हैं उन में एक बेरोजगारी की समस्या है, आर्थिक असमानता की समस्या है। अगर इन के संबंध में आप ने गंभीरता से विचार नहीं किया तो इस बार जो हवा आप को मिली है, और जिस को आप ने भी माना है कि वह हवा थी और उसी में बह कर आप जीते हैं, वह हवा दूसरी तरफ भी बह सकती है। देश की जनता कांग्रेस के ही साथ नहीं है। 50 परसेंट से कम ही वोटों के आधार पर आज जीत गये हैं···

श्री शीलभद्र याजी : खट्टा नोन कौन खाता है?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): He has a right to expres his opinion. It may be wrong.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE : What is the opinion? This is a wrong opinion.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप तो कुछ समझते नही है। बुद्धि की बात आप की समझ में आती ही नही है। मैंने तर्क दे कर कहा कि 1 करोड़ 12 लाख वोट हम को मिले और कांग्रेस को 6 करोड़ वोट मिले। हम को 22 सीटें मिलीं और हमारे दोस्तों को पौने चार सौ सीटें मिली। यह क्या है ? उपसभाध्यक्ष महोदय, वह बताता है कि किस अनुपात में जनता आप के साथ है।

श्री शीलभद्र याजी : एक वोट से भी अक्सरियत हो तो उसको अक्सरियत समझा जायेगा। यह समझिये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): Mr. Mathur, your time is up.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपने घंटी नहीं बजाई, आप घंटी बजायेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। बीच में याजी जी की आदत है कि बार-बार फुदक पड़ते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : मैंने घंटी बजाई थी।

श्री शीलभद्र याजी : मैं उनको पार्लिया-मेंटरी प्रैक्टिस समझाता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Mr. Mathur, you can take a minute or two more.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इसलिये, उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा मुख्य रूप से कि हमारे चुनावों की पद्धति है उस चुनाव पद्धति को बदला जाये, हमारी पंचवर्षीय योजनायें जो हैं उन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर इस प्रकार का परिवर्तन किया जाये और हमारे संविधान में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाय जिससे कि हर बेकार आदमी को रोजगार मिले और जो आर्थिक असमानता है वह आर्थिक असमानता दूर हो। चूंकि आप कहते हैं कि मेरा समय समाप्त हो गया है इसलिये मैं यहीं समाप्त करता हूं।

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में चुनावों के नतीजों का जिक्र कई मर्तबा किया है और हम यह उम्मीद करते थे कि उन नतीजों को लाने के लिये जो वायदा सत्तारूढ़ दल ने किया था उसे कार्यान्वित करने के लिये राष्ट्रपति महोदय उन नीतियों का निर्देशन करेंगे, उसकी रूप-रेखा प्रस्तुत करेंगे जिससे हम यह समझ सकते कि यह देश की गरीबी मिटाने के लिये अथवा समाजवाद लाने के लिये इस दिशा में सरकार को ले जाना चाहते हैं परन्तु, मान्यवर, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन कार्यक्रमों का कोई निर्देशन उसमें नहीं है। मैं याजी जी की राय से सहमत हूं कि समाजवाद को दिशा देने का जैसा वायदा कांग्रेस की सरकार अब तक इस देश में करती रही उसी प्रकार का एक और वायदा देश के सम्मुख केवल मृग मरीचिका के रूप में प्रस्तुत है और वह इस अभिभाषण में भी रखा गया है।

आखिरकार, मान्यवर, इस देश में पहले से ही कांग्रेस की सरकार रही है, केन्द्र में बराबर रही है, और उसी के प्रधान मंत्री भी रहे हैं, उसी की नीतियों के अनुरूप प्लानिंग कमिशन, योजना आयोग, चलता रहा और देश की अधिकांश सरकारें भी चलती रही हैं लेकिन जो सब से दुखद प्रकरण है कि बावजूद योजना आयोग के, बावजूद योजना के चलने के, देश में गरीबी बढ़ती गई, बेकारी बढ़ती गई और जो आर्थिक असमानता थी वह देश में निरन्तर बढ़ती गई। आज आप प्रिवी पर्स को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, राजाओं को खत्म करना

चाहते हैं, ठीक है लेकिन जो फ्युडलिज्म के, सामन्तवाद क, सामन्तशाही के प्रतीक थे वह राजा महाराजा तो एक तरह से खत्म हो चुके हैं, उनके साथ अब कुछ नहीं रहा है, किन्तु आज पूंजीवाद की देश में जो वृद्धि हो रही है, देश में जो बड़े-बड़े लोग, उद्योग-पति बढ़ रहे हैं, जिनकी पूंजी बढ़ रही है, चार सौ फीसदी से अधिक जिनकी पूंजी बढ़ी है इन नये पूंजीपतियों को समाप्त करना और उनकी बढ़ती हुई ताकत को घटाना हम समझते हैं कि आज की सरकार की क्षमता के परे है। इसका कारण, मान्यवर, यह है कि चुनाव को जो प्रक्रिया इस देश में अपनाई गई और जो चीजें इस निर्वाचन में सामने आई वह अत्यंत खेदजनक हैं।

आज रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स एक्ट में इलेक्शन कमिशन को उम्मीदवारों को तो अपने खर्चे का विवरण देना पड़ता हैं और, मान्यवर, मै पहले ही कह चुका हूं कि इस देश के उम्मीदवार सम्भवतः अधिकांशतः शतप्रतिशत गलत नहीं तो ऐसे इलेक्शन रिटर्न भरते हैं जो कि वास्तविक व्यय से कम के होते हैं लेकिन उसमें कुछ छूट मिल जाती है क्योंकि जो पोलिटिकल पार्टीज़ खर्च करती है उसका कोई हिसाब नही होता। इस चुनाव में सत्तारूढ़ दल ने और दूसरे दलों ने जिस प्रकार से रुपया खर्च किया उस खर्चे का इलेक्शन कमिशन के पास पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कोई रिटर्न भरा नहीं जाता और इनको पूरी छूट है कि पोलि-टिकल पार्टी अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिये जितना भी रुपया चाहें व्यय करें। मैं समझता हूं कि इस देश के जनतंत्र के लिये यह सब से खतरनाक चीज़ है। मान्यवर, जो सत्तारूढ़ दल है उसने अपने को कामयाब बनाने के लिये सरकारी साधनों का किस प्रकार से उपयोग किया अथवा दुरुपयोग किया वह सारा देश जानता है और सत्तारूढ़ दल ने कितने साधनों को चुनाव में लगाया यह स्वयं वह लोग जानते हैं और सारा देश जानता है। आखिरकार रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स एक्ट में उस तरह से तरमीम करनी चाहिये थी। अगर इस देश में गरीब लोगों का राज कायम करना है, आम जनता को और साधारण कार्यकर्ता को इसमें मौका देना है इलेक्शन में आने के लिये तो अब समय आ गया है कि रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स एक्ट में इस तरह की व्यवस्था की जाये कि पोलिटिकल पार्टीज़ जितना रुपया इलेक्शन में खर्च करें उसका भी रिटर्न दाखिल किया जाये और उसकी तफसील संसद् के सामने और देश के सामने आनी चाहिये।

मान्यवर, यह सही है कि कांग्रेस पार्टी के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल जी जो थे उन्होंने उस समय फैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर्स सरकारी साधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं।

ठीक है, और आज के चुनाव में मान्य-वर, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी तमाम सरकारी साधनों का उपयोग किया और जैसा मणि जी ने कहा, इस चुनाव में आपके पक्ष में अधिक साधन इकट्ठा थे और उन साधनों का उपयोग दूसरी पार्टियों के लिए खुला नहीं था। आल इंडिया रेडियो का जिस तरह उपयोग हुआ, वैसे ही टेलीविज़न का हुआ, अखबारों का हुआ, उससे मान्यवर, मैं समझता हूं कि सरकारी पक्ष ने खूब फायदा उठाया। अखबार सत्तारूढ़ दल के पक्ष में ही प्रचार करते रहे क्योंकि जो न्यूज एजेन्सीज़ हैं, तमाम उन सब को सरकार सब्सक्राइब करती है, रुपया देती है, उनको खरीदती है, उन अखबारों को सरकार इतना अधिक प्रचार की सामग्री देती है, उनके ऊपर निर्भर करती है। अपने प्रकासन को चलाने

[श्री श्याम लाल यादव]

के लिए उन सबने मिलकर किस प्रकार से आपका समर्थन किया है, यह मैं समझता हूँ, इलेक्शन कमीशन की बड़ी असफलता है, वह यह कि उन्होंने शुरू में प्रयास किया कि तमाम पार्टियों को सुविधा मिले, लेकिन सत्तारूढ़ दल ही इसमें सहमत नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कारण यह था कि उनके हाथ में सरकार थी, आल इंडिया रेडियो सरकारी सस्था है, इसलिए विरोधी दल के पक्ष में उसका उययोग हो ही नहीं सकता है इलेक्शन कमीशन चाहे या नहीं चाहे, इसलिए मान्यवर अगर इलेक्शन कमीशन को कामयाब बनाना है, राजनैतिक पार्टियों को सुविधा देनी है, तो चुनाव प्रचार के लिए सब पार्टियों को बराबर के अवसर मिलने चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में जो यह कहा कि निर्वाचन निष्पक्ष तरीके से हुए, यह यथार्थ से परे है। इलेक्शन कमीशन के, रूप में भी सुधार होना आवश्यक है। आज वह समय आ गया है, इलेक्शन कमीशन में कम से कम तीन सदस्य होने चाहिये और तीन सदस्य मिलकर ही देश के निर्वाचन कार्य को सम्पन्न करें क्योंकि वहां एक व्यक्ति की निष्पक्षता के बारे में देश के नागरिकों को संदेह हो गया है। और चुनाव के दौरान मान्यवर, जो अशांति हुई—आज ही यहां पर जो जवाब दिया गया उसको देखने से और जो हमें अनुभव में आया है उसके अनुसार यह जो सत्तारूढ़ दल के स्टान्गहोल्ड हैं, वहां पर चुनाव संचालन में अशांति हुई है—उसके अनुसार तामिलनाडु में 370 केसेज हुए, महाराष्ट्र में 45—उस प्रदेश की जनसख्या को देखे, लोकसभा की सीटों को देखे, उस की टेरीटरी को देखें, उस हिसाब से देखे—तो तामिलनाडु मे 370 केरल में 358 और वेस्ट बंगाल में तो 1,027, जहां पर कि सीधे आपकी हकूमत थी। तो मैं यह कहना चाहूंगा, चुनाव के पूर्व शांतिपूर्वक विरोधी पार्टियों को आपने चुनाव सभाओं का संचालन करने का अवसर नहीं दिया और इस तरह से अशांति पैदा की गई। इससे हम समझते हैं देश में, खासकर बिहार में, जैसा मान्यवर, कांग्रेस प्रेसीडेंट जगजीवनराम जी ने भी एक बयान दिया कि 50 पोलिंग बूथ पर उनके वोट नहीं पड़ने देते थे, वह रीपोलिंग होनी चाहिए। तो बूथ कन्ट्रोल की बात कही जाती है। जिसके पास साधन थे उन लोगों ने दुरुपयोग किया। इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं थी कि शांतिपूर्ण चुनाव हो पाएं और चुनाव सभाओं के द्वारा विरोधी दल अपना प्रचार कर सकें। इसलिए हम समझते हैं कि चुनाव की सभाओं में और चुनाव के समय जो इस तरह का प्रतिरोध करते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए और शांतिपूर्वक चुनाव प्रक्रिया चलनी चाहिए।

मान्यवर, हम तो समझते थे कि चुनावों के बाद देश में शांतिपूर्वक प्रजातंत्र को चलने दिया जाएगा लेकिन अब चुनावों के बाद एक दूसरी प्रक्रिया सत्तारूढ़ दल ने शुरू की, कि जो दूसरे दलों के लोग हैं उनमें तोड़-फोड़ करें, उनको प्रलोभन देकर अपने दल में मिलाएं और एक-एक आदमी को तोड़-फोड़कर अपने पास लाने की कार्यवाही हो रही है जिससे वहां के शासन को चलने नहीं दिया जाए। मान्यवर यह कोई नैतिकता नहीं रह गई है ··· (*Interruption*) ··· न मैं समझता हूं यह कोई प्रजातंत्र की बात है कि दूसरे दल के लोगों को बरगलाकर, फुसलाकर, प्रलोभन देकर, डिफेक्शन कराएं। और इस प्रकार से देश की कई सरकारों को मान्यवर गिराया जा रहा है। हम चाहते हैं ··· (*Interrup-*

tions) . . . हम चाहते है हमारी बातों को याजी साहब शांति से सुनें, समझें । मान्यवर चूंकि याज जरा पुराने व्यक्ति हैं इसलिए हम उनक आदर करते हैं । याजी जी को विशेषकर मैं कहता हूं कि इस विषय में मैंगनेनिमा होना चाहिए, गम्भीरता के साथ इस ो सोचना चाहिए । खाली नशा किसी के दिमाग में न चढ़ जाए, यह मैं अर्ज करना चाहता हूं क्योंकि हमारा पड़ोसी स लोन का देश है जहां श्रीमती भंडारनायके को बड़ी भारी विजय पिछले चुनावों मे मिली थी, लेकिन आज वहां पर क्या हालात हो रही है ? इमरजेन्सी डिक्लेयर करनी पड़ी, वहीं की जनता उनकी विद्रोही, सशस्त्र विद्रोही बदकर खड़ी हो गई है, मशस्त्र क्रांति करने को तैयार है । हमारे देश में आपका शासन पहले से था लेकिन सन् 1967 में देश में हवा पलटी और देश में कांग्रेस की और विरोधी दलों की सरकारें बनी । और आज आपने ऐसी हवा चलाई, अपने साधनों की भरपूर प्रयोग किया, और ठीक है, आपको कामयाबी हुई, हम उसको कबूल करते हैं ।

लेकिन मान्यवर, आप इस देश का शासन प्रजातंत्रीय तरीकों पर चलाने की कोशिश करें क्योंकि सत्ता हमेशा के लिए आपके हाथों में नहीं रह सकती है । इस देशकी जनता इतनी कमजोर नहीं है कि वह आपके भुलावे में आ जाय और आपके नारों में बही चली जाय । इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इन तमाम बातों के ऊपर सब्र के साथ विचार करें और जो वादे किये हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करें ।

आप कहते हैं कि हमें डैमोक्रेसी को चलाना है, तो मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि डिफेक्शन के बारे में सब पार्टियों की राय से जो मसविदा तैयार कर लिया गया था उसको आप कानून के रूप में क्यों नहीं लाना चाहते हैं । आपके पास साधन हैं इसलिए आपने प्रदेशों के एम० एल० एज० को तोड़-तोड़ कर अपनी तरफ कर लिया है । कम से कम अब तो आप डिफेक्शन के संबंध में कानून लागू करिये । आज आप इसकी जरूरत नहीं समझते हैं । अगर आप इसकी जरूरत समझते, तो राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में इसका जिक्र करते । उन्होंने भी इस चीज की जरूरत महसूस नहीं की । (*Interruption*) उनकी बीच में कहने की आदत बन गई है और इस तरह से वे विघ्न पैदा करते रहते हैं । आपके पास मेजारिटी है और हम लोग अल्प संख्या में हैं और हमारी बात को सुनने का आपका फर्ज होना चाहिये तथा सब्र होना चाहिये चाहे हमारी बात गैर मुनासिब हो या सही हो । आपको हमारी बात का जवाब समय पर देना चाहिये और जो आपका जवाब होगा उसको हम सहर्ष सुनेंगे । मै कह रहा था कि अगर हमें प्रजातंत्र को मजबूत बनाना है, तो हमें डिफेक्शन के संबंध में जल्द से कानून लाना चाहिये, लेकिन राष्ट्रपति जी ने जानबूझ कर इस बात का जिक्र अपने अभिभाषण में नही किया है क्योंकि देश में कई प्रदेशों की सरकारों को गिराना था और इसके लिए डिफेक्शन का सहारा लेना था ।

आप संविधान को बदलने की बात कहते है, सो ठीक है । आप समझते है कि कमिटेड ज्यूडिशरी होनी चाहिये, ऐसी ज्यूडिशरी होनी चाहिये जो कानून संसद पास करे वह उसके लफज को न देखे, उसकी व्याख्या न करे बल्कि जो कानून बनता है उसको सही मान ले । ठीक है आप इस तरह से संविधान में परिवर्तन कर सकते है। लेकिन मैं यह निवेदन

[श्री श्याम लाल यादव]

करना चाहता हूं कि जिस दिन हिन्दुस्तान में इस तरह से संविधान में परिवर्तन करने की कोशिश की जायेगी, ज्यूडिशरी को स्वंतत्र नहीं रहने दिया जायेगा, कमिटेड ज्यूडिशरी की स्थापना की कोशिश की जायेगी, उस दिन इस देश में जनतंत्र नहीं रह सकेगा और ज्म्हूरियत का जनाजा उठ जायेगा।

इसके साथ ही साथ मैं भ्रष्टाचार के संबंध में भी अर्ज करना चाहता हूं। आज प्रसाशन में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में इतना भ्रष्टाचार फैल गया है कि यह चीज यहां के वायू और हवा में इतनी फैल गई है कि इसकी चर्चा राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में करने की जरूरत नहीं समझी। शायद राष्ट्रपति जी भी इसको चर्चा करना गुनाह समझते है। भ्रष्टाचार के संबध में सरकार ने खुली छूट दे दी है, और वह इसकी और कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं समझती है।

आज हमारे देश के विकास की जो प्रगति हो रही है और पिछले दो सालों में इस सरकार ने उद्योग, परिवहन की जो अवनती की है, जो कमी इन चीजों मे आई है, जो गिरावट आई है, उसको सरकार स्वंय तसलीम करती है। मान्यवर जिन उद्योगों से सरकार को टैक्स मिलता था उन उद्योगों का वह राष्ट्रीयकरण करती है। उन उद्योगों, उन कम्पनियों को सरकार अपने हाथ में ले रही है जो बराबर घाटे में चलते आ रहे हैं और इस तरह से टैक्स लगाकर सरकार जनता के ऊपर इन कंपनियों का भार भी डाल रही है।

मैं श्री याजी की इस बात से सहमत हूँ कि पब्लिक सैक्टर में जिन आई० ए० एस० और आई० सी० एस० आफिसरों को लगाया गया है उन्हे नही लगाया जाना चाहिये क्योंकि उन्हें जनता से कोई मुहब्बत नहीं होती है। वे लोग तो अपनी नौकरियों को देखते हैं और इस तरह की कोशिश करते है जिससे काम बढ़ता ही चला जाये ताकि उनकी नौकरी आगे बढ़ती चली जाये। इस तरह की इन आफिसरो की भावना होती है और में समझता हूं कि किसी भी उद्योग में सफलता मिलना सम्भव नही है जब तक इस तरह के आफिसर रहेंगे क्योंकि अभी तक का तो अनुभव यही बतलाता है। अगर इस चीज पर रोक नही लगाई गई, तो आने वाले जमाने में भी सरकार को इन उद्योगों से घाटा ही होगा।

रेलवे में मान्यवर, कर्मचारी बढ़ते ही चले जा रहे हैं, यह बात ठीक है। लेकिन रेलवे में जो कर्मचारी हैं उनकी सुविधाओं और उनके नियंत्रण के संबंध में भी विशेष ख्याल रखना होगा। मै समझता हूं कि कांग्रेस को जो मासिव विक्ट्री मिली है उससे कुछ मंत्रियो के ऊपर भी असर पड़ा है। श्री हनुमन्तैया ने कहा कि जो रेलवे को एम० पीज० पत्र लिखते हैं वह ठीक नही है और इस तरह से वे बुरा मान गये। इससे पहले वे एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्म कमिशन के चेयरमैन रह चुके है और इसके भी पहले वे मैसूर के मुख्य मंत्री रह चुके है। मैं समझता था कि वे प्रगति की बात करेंगे लेकिन उनका दिमाग भी उल्टा बहने लगा है। रेलवे विभाग के पास एम० पीज० ने जो तीन हजार पत्र लिखे हैं, जिन्हें नन्दा जी के जमाने में लिखा गया उससे वे नाराज हो गये। मैं समझता हूं कि जब रेलवे कर्मचारियों के साथ रेलवे बोर्ड वाले दक्यिानूसी वर्ताव करते

है तब वे लोग जनता के प्रतिनिधियों के सामने आते है और अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए वे एम० पीज० से कहते है। श्री नन्दा जी की इस मामले में प्रशंसा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मामले में संसद के सदस्यों का विशेष ख्याल रखा और उनकी बातों के ऊपर तवज्जो दी।

6 P.M.

मुगलसराय में एक लाख रुपए की प्रतिदिन चोरी होती थी लेकिन नन्दा जी का आपरेशन मुगलसराय चलने के बाद ——मैं वहाँ का रहने वाला हूं, वहां के लोगों से ताल्लुक है—चोरी में काफी कमी हुई, उसका असर हुआ, उसका श्रेय उनको मिलना चाहिए। जब से हनुमन्तैया जी आए हैं रेलवे कर्मचारियों की समझ में आ गया है कि एक अफसर आ गया है जो हमारी बातों को सुनता रहेगा, जनता के प्रतिनिधियों की बातें नहीं सुनेगा। सूचना आ रही है कि धीरे-धीरे चोरियां फिर वहां होने लगी हैं। हनुमन्तैया जी इस विभाग को संभालेंगे, तो शायद रेलवे का प्रशासन और खराब हो जायेगा।

आखिर में मैं एक-दो बातें और निवेदन करना चाहता हूं। समाजवाद बहुत सुन्दर शब्द है, अगर समाजवाद आएगा और उससे गरीबों के घरों में रोशनी होगी, तो हमें बुरा लगेगा। जो पिछड़े हुए लोग हैं; बैकवर्ड क्लासेज है उनको भी तरजीह दी जानी चाहिए, इस शासन का जो रुपया बंट रहा है नौकरियों के माध्यम से, अरबों, खरबों रुपया उसमें बैकवर्ड क्लासेज को भी स्थान मिलना चाहिए। आज देश की आजादी के बाद, प्लानिंग की योजनाएं चलने के बाद बैकवर्ड क्लासेज नौकरियों से हटते जा रहे है, ऊंची नौकरियों में नगण्य होते जा रहे है। इसलिए हम इस बात की जोरदार मांग करते हैं कि बैकवर्ड क्लासेज को सर्विसेज में रिजर्वेशन मिलना चाहिए।

सुरक्षा नीति के सम्बन्ध में हम इतना ही निवेदन करना चाहते है कि डिफेंस जातियों के नाम पर रेजिमेंटस खत्म करने की बात चल रही है। कई जातियों के नाम पर रेजीमेंट्स हैं। उन जातियों ने जिन्होंने देश की रक्षा में, काश्मीर की लड़ाई में त्याग का उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया है, जिन्हें मार्शल रेसेज भी कहते हैं, उनके नाम पर अगर रेजिमेंट बनाने की मांग होती है, तो सुरक्षा मंत्री उसे मंजूर नहीं करते। हम समझते हैं कि यह उनकी सदाशयता के विपरीत है। इन जातियों के लोग देश के लिए त्याग कर रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर मिलिट्री में आप जातियों के नाम पर रेजिमेट्स खत्म कर रहे हैं, तो खत्म होनी चाहिए लेकिन अगर रखते हैं, तो उन जातियों के नाम पर भी होनी चाहिये, जैसे अहीर रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट, जिन्होंने देश के लिए सबसे अधिक नाम कमाया है।

विदेशी नीति के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी नीति हो वह हमारे देश के हितों को ध्यान में रखते हुए हो। आज ईस्ट बंगाल का सवाल है, पूर्वी पाकिस्तान का हमने संसद में एक प्रस्ताव पास किया, उसके साथ हम है लेकिन हम यह समझते हैं कि ईस्ट बंगाल के मामले में शायद भारत सरकार हिचक रही है, हिम्मत के साथ काम करने की उसमें कमी है। इसी कारण उन्होंने ऐसा प्रस्ताव संसद से पास किया और जो याजी जी की भावना है, जो याजी जी चाहते हैं। उसमें एग्री करने को वे आगे नहीं बढ़ रहे है।

एक माननीय सदस्य : याजी जी चले गए।

श्री श्याम लाल यादव : यह दूसरे की बात क्यों सुनें, अपनी बात सुना गए। इसी

[श्री श्याम लाल यादव]

प्रकार प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान के अन्दर यह झगड़ा हो रहा है, उसकी टेरीटरी है, उसके अन्दर यह अपनी सावरेनटी, अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ाई हो रही है, एक तरह से यह इन्टर्नल मामला भी है। दूसरी तरफ यह वैसा भी मामला है जैसा हमारा काश्मीर का मामला था हम जानते हैं कि काश्मीर में पाकिस्तान ने क्या किया। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि 1965 में संसद् ने एक प्रस्ताव पास किया था और चव्हाण साहब आए थे महाराष्ट्र से बम्बई से उन्होंने एलान किया था कि जब तक उस धरती को वापस नहीं ले लूंगा बम्बई वापस नहीं जाऊंगा. उसके बाद हजार दफा वापस गए, वह भी भूल गए, सुरक्षा मंत्री थे अब वित्त मंत्री हैं, संसद भी भूल गई, सरकार भूल गई, सारा देश भूल गया। वह प्रस्ताव पास किया था कि भूमि को वापस लेने का लेकिन वह प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं किया गया। इसी तरह से यह प्रस्ताव हुआ। यह अन्दरूनी मामला पाकिस्तान का हो सकता है, दूसरी तरफ काश्मीर का उदाहरण भी है। आज इस सरकार में अगर हिम्मत हो, अगर वह इस देश के नागरिकों के मत का आदर करना चाहती है तो उसे हिम्मत के साथ ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे देश का कल्याण हो सके और उसके हितों की सुरक्षा हो सके।

ALLOTMENT OF TIME FOR GOVERNMENT LEGISLATIVE AND OTHER BUSINESS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held on the 1st April 1971, allotted time as follows for Government legislative and other business to be taken up during the current session of the Rajya Sabha:

Consideration of the motion regarding conduct of Shri Rajnarain and others on the solemn occasion of the President's Address to both Houses of Parliament.	1 hour 30 minutes (to be taken up on 7th April '71).
Consideration of a motion for reference of the Advocates (Amendment) Bill, 1971, to a Joint Committee of both Houses.	1 hour.
Discussion of the Resolution seeking approval of the Notification (G.S.R. No. 152), dated the 29th January 1971, declaring the service in the Food Corporation of India to be an essential service.	1 hour 30 minutes.
Consideration of the motion regarding annulment of the Conduct of Elections (Second Amendment) Rules, 1971.	2 hours.

The House stands adjourned till 11 00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at three minutes past six of the clock till eleven of the clock on Friday, the 2nd April, 1971.